



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 27 जून, 2009 / 6 आषाढ़, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जून, 2009

संख्या ई०डी०एन०-ए०-क(१)-२१/२००७.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ईटरनल विश्वविद्यालय, बड़ू साहिब, हिमाचल प्रदेश के प्रथम परिनियम निम्नलिखित रूप में बनाती हैं, अर्थात्:—

ईटरनल विश्वविद्यालय, बड़ू साहिब, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के प्रथम परिनियम

1. संक्षिप्त नाम.—इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम ईटरनल विश्वविद्यालय, बड़ू साहिब, हिमाचल प्रदेश के प्रथम परिनियम, 2009 है।

(2) ये परिनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन परिनियमों में जब तक कि कोई बात, विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो,—

(i) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 3) अभिप्रेत है;

(ii) "प्राधिकरण" से विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(iii) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी हैं चाहे वे अध्यापन या अध्यापनेतर हों;

(iv) "अधिकारी या अधिकारियों" से विश्वविद्यालय के अधिकारी अभिप्रेत हैं;

(v) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) समस्त शब्दों और पदों के जो इन परिनियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए हैं।

3. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी—धारा 11 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य व्यक्ति विश्वविद्यालय के घोषित अधिकारी होंगे:—

(i) शैक्षणिक क्रियाकलाप का अधिष्ठाता (डीन ऑफ अकैडमिक अफेयरज);

(ii) संकाय अधिष्ठाता (डीन ऑफ फैकल्टी);

(iii) अध्ययन अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्टडीज);

(iv) छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्टुडेन्ट्स वैलफेरज);

(v) स्नातकोत्तर अध्ययन अधिष्ठाता (डीन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज);

(vi) सहकारी अध्ययन तथा नियोजन अधिष्ठाता (डीन ऑफ कोऑपरेटिव स्टडीज एण्ड प्लेसमेंट);

(vii) दूरवर्ती विद्या/शिक्षा अधिष्ठाता (डीन ऑफ डिस्टैन्स लर्निंग/एजूकेशन);

(viii) परीक्षा नियन्त्रक;

(ix) पुस्तकालाध्यक्ष।

4. कुलाधिपति की सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा शक्तियां और कृत्य—(1) कुलाधिपति धारा 12 की उपधारा (4) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात्:—

(क) कुलाधिपति शासी निकाय का अध्यक्ष होगा;

(ख) कुलाधिपति को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निर्दिष्ट करे, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था या इसके संकाय/विद्यालय/महाविद्यालय का, उसके भवनों, प्रयोग शालाओं, अभिलेख या उपस्कर सहित, और इसके द्वारा संचालित और करवाई गई परीक्षाओं, अध्यापन और अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवाने का या उसी रीति में विश्वविद्यालय या उस द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय की बाबत जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(ग) विश्वविद्यालय या उस द्वारा अनुरक्षित संस्था/विद्यालय/महाविद्यालय के किसी भी क्रियाकलाप से सम्बन्धित निरीक्षण या जांच की दशा में कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम, उस पर अपने मत (दृष्टिकोण) सहित, कुलपति को संसूचित कर सकेगा और उस पर कार्रवाई किए जाने की बाबत परामर्श देगा, जैसी कुलाधिपति प्रस्थापना करे तथा कुलाधिपति द्वारा दी गई रिपोर्ट की प्राप्ति पर, कुलपति, निरीक्षण या जांच का परिणाम और कुलाधिपति का मत और उस पर की जाने वाली कार्रवाई पर उस द्वारा दिए गए परामर्श को तत्काल प्रबन्ध बोर्ड को सूचित करेगा और प्रबन्ध बोर्ड कुलपति के माध्यम से ऐसे निरीक्षण या परिणामों पर ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जिसका करना वह प्रस्तावित करे या जो उस द्वारा की गई हो, कुलाधिपति को संसूचित करेगा।

(घ) जहां, यथास्थिति, प्रबन्ध बोर्ड या संकाय/विद्यालय/महाविद्यालय का प्रबन्धन कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करता है, तो कुलाधिपति, यथास्थिति, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी करेगा जैसे वह उचित समझे तथा विश्वविद्यालय या संकाय/विद्यालय/महाविद्यालय ऐसे निदेशों की अनुपालना करेगा।

(ड) पर्वूगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति लिखित में आदेश द्वारा विश्वविद्यालय या इसके किसी प्राधिकरण (अर्थात् अधिकारी) की कार्यवाहियों को या विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के ऐसे विनिश्चय को बातिल (निष्प्रभाव) कर सकेगा जो अधिनियम या विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए पश्चात् वर्ती परिनियमों के अनुरूप न हो :

परन्तु ऐसा आदेश करने से पूर्व कुलाधिपति विश्वविद्यालय या, यथास्थिति, इसकी शैक्षणिक इकाई, इसके प्राधिकरण या अधिकारी को कारण बताने हेतु बुलाएगा कि क्यों ऐसा आदेश नहीं किया जाना चाहिए और यदि उस द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कारण बता दिया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

(2) जब कुलाधिपति मुख्यालय से बाहर है या बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो कुलपति, और यदि कुलपति का पद भी रिक्त है, तो ऐसा व्यक्ति, जिसे कुलाधिपति नियुक्त करे, कुलाधिपति के कर्तव्यों का पालन करेगा तथा, यथास्थिति, कुलपति, या कुलाधिपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति पूर्वतर अवसर पर, उस द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पुष्टि के लिए कुलाधिपति को करेगा :

परन्तु यदि की गई कार्रवाई का अनुमोदन नहीं किया जाता है तो कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

5. कुलपति की सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा शक्तियां और कृत्य।—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कुलपति किराया संदर्भ किए बिना आवास और उसके पूर्ण रख-रखाव के लिए हकदार होगा।

(3) कुलपति, कुलाधिपति को सम्बोधित, स्वहस्ताक्षरित एक मास के लिखित नोटिस द्वारा अपना पद त्याग सकेगा:

परन्तु जहां समुचित आधार हों तो कुलाधिपति नोटिस की अवधि का अधित्यजन करके त्यागपत्र को तत्काल स्वीकार कर सकेगा।

(4) यदि कुलपति का कार्यालय त्यागपत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है तो कुलाधिपति अपनी पसन्द के किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जो कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन, तब तक करेगा जब तक, यथास्थिति, स्थाई आधार पर रिक्त भरी नहीं जाती है या जब तक कुलपति अपने कर्तव्यों

को फिर से संभाल नहीं लेता, और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को कुलपति की समस्त शक्तियां होंगी तथा वह कुलपति के विशेषाधिकारों का हकदार होगा:

परन्तु ऐसी अंतरिम व्यवस्था ऐसी व्यवस्था के किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि से अधिक के लिए नहीं होगी।

(1) कुलपति, अधिनियम की धारा 13 के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग तथा पालन करेगा, अर्थात्:—

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की किसी भी बैठक में उपस्थित होने और उसको सम्बोधित करने का हकदार होगा।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियन्त्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के विनिश्चयों को पूर्ण अभिप्राय से प्रभाव देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे प्रकृति और व्यवहार में विरोधात्मक न हों।

(4) कुलपति के पास ऐसी समस्त शक्तियां होंगी जो विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हों और वह ऐसी किन्हीं शक्तियों को ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा जिन्हें वह उचित समझे।

(5) कुलपति, अधिष्ठाताओं (डीनज), प्राचार्यों, आचार्यों, सह आचार्यों, रीडरों (उपाचार्यों), प्राध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्ष, अन्य शिक्षकों और विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संकाय/विद्यालय/महाविद्यालयों और संस्थाओं के ऐसे शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की, प्रयोजन के लिए कुलाधिपति द्वारा गठित समितियों की सिफारिशों पर, नियुक्तियां करेगा जो आवश्यक हों। कुलपति ऐसी समितियों का अध्यक्ष होगा:

परन्तु कुलपति ऐसे व्यक्तियों की, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, लघु अवधि की नियुक्तियां कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के कृत्यों के लिए आवश्यक समझी जाएं।

(6) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान करेगा और उसकी अनुपस्थिति के दौरान, ऐसे अधिकारी के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।

(7) कुलपति, विनिर्दिष्ट रीति में विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान करेगा और यदि वह ऐसा विनिश्चय करता है, तो वह ऐसी शक्तियों को विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(8) कुलपति, को पश्चात्वर्ती परिनियमों में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का प्राधिकार होगा:

परन्तु यदि कुलपति की रिपोर्ट पर, प्राधिकरण या निकाय द्वारा लिया गया विनिश्चय विश्वविद्यालय की सेवा में रत किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वह व्यक्ति उस तारीख जिसको उसे विनिश्चय संसूचित किया गया है से तीस दिन के भीतर कुलाधिपति को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

(9) कुलपति, को शासी निकाय को छोड़कर विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों/निकायों की बैठकें बुलाने या बुलाए जाने की शक्ति होगी।

(10) यदि कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव शीघ्र अवसर पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होता:

परन्तु यदि सम्बोधित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी थी तब ऐसा मामला कलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(11) कुलपति, यू० जी०सी०, ए०आ॒ई०सी०टी०ई०, एन०सी०टी०ई०, स्थापत्य कला परिषद्/विश्वविद्यालयों/फार्मसी परिषद्, एन०ए०ए०सी०/एन०बी०ए०, अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों तथा अन्य विनियामक निकायों के साथ एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेगा। सरकारी विभागों, जिससे विश्वविद्यालय को व्यवहार करना है, से अच्छे और सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रखने के लिए हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशालय के साथ सम्पर्क रखना;

(12) कुलपति संस्थाओं के लिए उच्चतर सम्भव ग्रेड प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन करने तथा सभारततन्त्र संभाल (लॉजिस्टिक स्पोर्ट) उपलब्ध करवाने हेतु संस्थाओं और विभागों के लिए एन०ए०ए०सी०/एन०बी०ए० प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु पग उठाएगा और प्राप्त करेगा। यू० जी०सी०, ए०आ॒ई०सी०टी०ई०, राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों सहित निधियां उपलब्ध करवाने वाले विभिन्न अभिकरणों से वित्तीय अनुदान की अधिकतम रकम लेने में विभागों और संस्थाओं की सहायता करेगा;

(13) राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार की नवीनतम शैक्षणिक पॉलिसियों के साथ नई जानकारी से अपने को अवगत रखना तथा उसके बारे में विभाग/संस्थाओं को भी अवगत कराना, उनके उचित कार्यान्वयन में उनका मार्गदर्शन करना;

(14) कुलपति, प्रत्यके शैक्षणिक वर्ष की समाप्त होने पर पश्चात्वर्ती परिनियमों या अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट रीति में संकाय के सदस्यों द्वारा किए गए अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य का निर्धारण और मूल्यांकन करेगा, यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से करेगा। ऐसे निर्धारण या मूल्यांकन पर, यदि कुलपति की राय में संकाय के किसी सदस्य का कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं है तो वह पश्चात्वर्ती परिनियमों या अध्यादेशों में अधिकथित रीति में, ऐसे सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करेगा या करवाएगा।

(15) कुलपति, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए पश्चात्वर्ती परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए; और

(16) कुलपति, यह देखेगा कि अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से अनुपालन किया जा रहा है तथा वह ऐसा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समस्त आवश्यक पग उठाएगा।

6. रजिस्ट्रार की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य.—(1) रजिस्ट्रार को, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर पश्चात्वर्ती परिनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सेवा के निबन्धनों और शर्तों पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त है और रजिस्ट्रार बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से अनुपस्थिति के कारण अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति, कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन, नियुक्त करे।

(3) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलपति के नियन्त्रणाधीन कार्य करेगा।

(4) रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड तथा विद्या परिषद् का पदेन सदस्य सचिव होगा परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(5) रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह—

- (क) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करे;
- (ख) समस्त पाठ्य विवरण, पाठ्यक्रम और उनसे सम्बद्ध सूचना का स्थायी अभिलेख रखे;
- (ग) ऐसी परीक्षाओं, जो पश्चात्वर्ती परिनियमों द्वारा उपबंधित की जाए, के संचालन हेतु परीक्षा नियन्त्रक की सहायता करे;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त समस्त उपाधियों, डिप्लोमां तथा शिक्षा सम्बन्धी उपाधियों (अकैडमिक डिस्टिंक्शन्ज) का रजिस्टर बनाए रखें;

(ङ) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और अन्य सम्पत्तियों, जिन्हें कुलाधिपति उसके भारसाधन में सौंपे, के अभिलेख की अभिरक्षा ले;

(च) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठकों की कार्यसूची की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाएं, दे, और प्राधिकरणों की बैठकों के कार्यवृत्तों की प्रतियां, साधारणतया ऐसी बैठकों को करने के एक मास के भीतर दें;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों में या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामें पर हस्ताक्षर करे और इस प्रयोजन के लिए अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करे;

(ज) विश्वविद्यालय की ओर से करार/संविदाएं करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करे; और

(झ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करे जो उसे समय—समय पर कुलपति और कुलाधिपति द्वारा सौंपे जाएं।

7. मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य——(1) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति जिसकी अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी, की सिफारिशों पर, पश्चात्वर्ती परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट सेवा के निबन्धनों और शर्तों पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(2) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा कुलपति के नियन्त्रणाधीन कार्य करेगा ।

(3) जब मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी का पद रिक्त है या जब मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से अनुपस्थिति के कारण अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे प्रयोजन के लिए कुलपति नियुक्त करे। नियुक्ति एक वर्ष के लिए रहेगी या जब तक कि उसके स्थायी प्रतिस्थापन को कुलाधिपति द्वारा नियुक्त नहीं कर दिया जाता ।

(4) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की निधियों पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगा और उसकी वित्तीय नीति के सम्बन्ध में उसे परामर्श देगा;

(ख) विश्वविद्यालय के लेखों के उचित रख—रखाव के लिए उत्तरदायी होगा; और

(ग) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे जाएं जो विश्वविद्यालय के पश्चात्वर्ती परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

(5) कुलपति के नियन्त्रण के अध्यधीन मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में से किसी को अग्रसर करने के लिए न्यास और विन्यास सम्पत्ति सहित, सम्पत्ति और विनिधानों को धारण करेगा और उनका प्रबन्ध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए नियत सीमाओं से अधिक न किया जाए और समस्त धन का व्यय उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाए जिनके लिए वह मंजूर या आबंटित किया गया है;

(ग) अगले वित्तीय वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और बजट तैयार किए जाने और उन्हें प्रबन्ध बोर्ड को, कुलपति के माध्यम द्वारा प्रस्तुत किए जाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा कि वित्तीय मंजूरियां समय पर अभिप्राप्त कर ली जाएं;

(घ) नकद और बैंक अतिशेषों की स्थिति और विनिधानों की स्थिति पर, बराबर नजर रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के विषय में परामर्श देगा;

(च) विश्वविद्यालय के समस्त धन को प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुसूचित बैंक में रखेगा;

(छ) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों, भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपस्करों के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित समस्त कार्यालयों, अध्यापन विभागों, संकाय/विद्यालय/महाविद्यालयों और संस्थाओं में उपस्करों और उपभोग्य सामग्री के स्टॉक का निरीक्षण नियमित अन्तरालों पर, या जैसा समय-समय पर अपेक्षित हो, किया गया है;

(ज) विश्वविद्यालय के अधीन किसी भी कार्यालय या विभाग या संकाय/विद्यालय/महाविद्यालय या संस्था से कोई ऐसी सूचना या विवरणियां मंगवाएगा जिन्हें वह अपने वित्तीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में आवश्यक समझे; और

(झ) कार्यसूची तैयार करेगा और जारी करेगा और वित्त समिति की बैठकों के कार्यवृत्त बनाए रखेगा और वित्त समिति की ओर से पत्र-व्यवहार का संचालन करेगा।

(6) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी या कुलाधिपति द्वारा इस नियमित प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय को संदेय धन के लिए जारी रसीद उस धन के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी।

8. अध्ययन अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्टडीज) की नियुक्ति, उसकी सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और वृत्त्य।—(1) कुलाधिपति द्वारा प्रत्येक संकाय/विद्यापीठों (स्कूल ऑफ स्टडीज) में, चयन समिति जिसकी अध्यक्षता कुलपति द्वारा की गई हो, की सिफारिशों पर अध्ययन अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्टडीज) नियुक्त किया जाएगा।

(2) कुलपति के अनुमोदन के अध्यधीन प्रत्येक अधिष्ठाता (डीन) ऐसे व्यक्तियों में से, जो विश्वविद्यालय के शिक्षक हों या रहें हों, जो रीडर (सह आचार्य) की पंक्ति से नीचे का न हो, या अनुसंधान तथा उद्योग में समतुल्य अनुभव रखते हों, कुलपति द्वारा, प्रयोजन के लिए गठित समिति, जिसकी अध्यक्षता उसने की हो, की सिफारिशों पर, नियुक्त किया जाएगा।

(3) जब अध्ययन अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्टडीज) का पद रिक्त हो या जहां अधिष्ठाता अपनी अनुपस्थिति द्वारा या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा पदाभिहित तथा कुलाधिपति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(4) अध्ययन अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्टडीज), संकाय/विद्यापीठों (स्कूल ऑफ स्टडीज) में अध्ययन (शिक्षण) और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) अध्ययन अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्टडीज) की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जो पश्चात्वर्ती परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उपबंधित की जाए।

9. परीक्षा नियन्त्रक की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य—

(1) परीक्षा नियन्त्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और चयन समिति, जिसकी अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी, की सिफारिशों पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) परीक्षा नियन्त्रक की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जो विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या अन्य अधिकारियों की हैं।

(3) परीक्षा नियन्त्रक कुलपति के अनुमोदन से निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा। वह कुलपति के सीधे नियन्त्रण के अधीन कार्य करेगा/करेगी, अर्थात्—

- (i) विश्वविद्यालय के विनियमों और नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए व्यवस्था करना और कार्य का सर्वेक्षण करना;
- (ii) ऐसे अन्य कर्तव्यों, जो पश्चात्वर्ती परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों और नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं या जो कुलपति या कुलाधिपति द्वारा अपेक्षित हों, का पालन करना;
- (iii) विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं का संचालन करना और परीक्षाओं के लिए प्रारम्भिक इंतजाम करना, परीक्षा केन्द्रों की स्थापना करना, पर्यवेक्षण और अधीक्षण तथा अन्य कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) की नियुक्ति करना, परीक्षाओं का अबाध, दक्ष, स्वच्छ और पारदर्शिक संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण और आपूर्ति तथा केन्द्रों से प्रयोग की गई 'उत्तर पुस्तिकाओं' को वापस प्राप्त करना, सुनिश्चित करना;
- (iv) परीक्षकों/पेपर सैटरों द्वारा विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र यह सुनिश्चित करते हुए कि तैयार किए गए प्रश्न पत्र परीक्षाओं की अनुमोदित स्कीम के अनुसार और विशिष्ट विषय/पेपर के लिए विहित पाठ्यक्रम के अनुसार हैं, तैयार करवाना। प्रश्न पत्र तैयार करने के समस्त चरणों की सम्पूर्ण प्रक्रिया की गोपनीयता सम्पूर्णतः रखी जाए;
- (v) प्रश्न पत्रों को ख्याति प्राप्त लेकिन गोपनीय मुद्रणालयों से मुद्रित करवाना। मुद्रणालय का नाम और पता, फोन नम्बर आदि गोपनीय रखे जाएं। मुद्रित प्रश्न पत्र, परीक्षा के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्राप्त कर लिए जाएं ताकि ये परीक्षा केन्द्रों में ठीक समय में पहुंच जाएं। सम्पूर्ण परिवहन प्रक्रिया भी, प्रश्न पत्रों के किसी प्रकार के प्रकटन (लीकेज) से बचाने के लिए गोपनीय रखी जाए;
- (vi) विभिन्न परीक्षाओं के प्रारम्भ की तारीखें नियत करना, आगामी एक वर्ष के दौरान होने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए डेटशीट और अनुसूची तैयार करना और समस्त सम्बद्ध की सूचना के लिए समय पर उसे प्रकाशित करवाना;
- (vii) विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाना ताकि ऐसे समस्त मामलों में अवार्ड लिस्टें (नम्बरों की सूचियाँ), परीक्षा शाखाओं/कम्प्यूटर सेक्षन में सारणीयन, संवीक्षा और विभिन्न परीक्षा परिणामों की घोषणा के लिए भेजी जाए। यह सुनिश्चित करना कि समस्त परीक्षा परिणाम प्रयोजन के लिए नियत समय (टाइम शेड्यूल) पर घोषित और प्रकाशित हो जाएं और जनसाधारण को व्यापक रूप से तदानुसार सूचित कर दिया जाए, परिणामों का संशोधन, उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच (री चैकिंग) और पुनर्मूल्यांकन जहां कहीं अपेक्षित हो, अनुज्ञेय होगा;
- (viii) विश्वविद्यालय से पास होकर जाने वाले समस्त छात्रों के लिए अंक तालिका के ब्यौरे (डिटेलड मार्कस कार्ड) उपाधियां और अन्य सुसंगत शंसापत्र (टेस्टीमोनियलज) तैयार करवाना और उनका उस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट अवधि में छात्रों/संकाय/विद्यालय/महाविद्यालयों/संस्थाओं को आपूर्ति (प्रदाय) करना;

(ix) उन छात्रों, जो विश्वविद्यालय से पास होकर गए हैं तथा भारत या विदेश में या तो काम (जॉब) के लिए या प्रवेश हेतु आवेदन करते हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा अपने प्रत्यय पत्रों को सत्यापित करवाना चाहते हैं, के प्रत्यय पत्रों के सत्यापन के लिए प्रबन्ध करना;

(x) गोपनीय निधियों के लिए लेखे तैयार करना और रखना, उन्हें विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चैक/प्रतिहस्ताक्षरित कराना और समस्त ऐसे गोपनीय संव्यवहारों/लेखों के लिए स्थायी अभिलेख बनाए रखना;

(xi) निरन्तर परीक्षा सुधारों के लिए पग उठाना ताकि परीक्षाओं से सम्बन्धित विद्यमान परिनियमों, विनियमों और नियमों को अद्यतन किया जा सके, परीक्षाओं से सम्बन्धित नए नियम और विनियम प्रस्तावित करना और उन्हें विश्वविद्यालय के सम्बद्ध निकायों से अनुमोदित करवाना;

(xii) विभिन्न परीक्षाओं, जिनमें परम्परागत और प्रवेश परीक्षाएं भी हैं, के परीक्षकों, पेपर सैटरों, मूल्यांकन करने वालों, केन्द्र अधीक्षकों (सेन्टर सुपरीटेडेन्ट्स), केन्द्र निरीक्षकों (सेन्टर इन्सपेक्टरज), उड़न दस्तों के सदस्यों, प्रेक्षकों, चीफ कोऑर्डिनेटरों, कोऑर्डिनेटरों की सूची तैयार करना और उसे, समुचित पुनरीक्षणों, यदि कोई हों, सहित विश्वविद्यालय के सक्षम निकायों द्वारा अनुमोदित करवाना;

(xiii) अंक तालिका के ब्यौरों (डिटेलड मार्क कार्ड्स), उपाधियों और समस्त अन्य प्रमाण पत्रों तथा शंसापत्रों को जब कभी ऐसा करना अपेक्षित हो, हस्ताक्षरित करना। गोपनीय मुद्राओं (सीलज), हस्ताक्षर वाली स्टैम्प सहित स्टैपें तैयार करवाना और अपेक्षित समय पर प्रयोग के लिए उन्हें अभिरक्षा में रखना। परीक्षा नियन्त्रक का यह सुनिश्चित करना दायित्व होगा कि इन गोपनीय मुद्राओं (सीलज), का किसी व्यक्ति द्वारा किसी अंतररक्ष्य प्रयोजन के लिए दुरुपयोग न हो या टैम्पर्ड या गुम न हो जाएं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पर डयूप्लीकेट अंक तालिका ब्यौरे (डी०एम०सी०) और उपाधियां अपेक्षित फीस के संदाय पर जारी की जाएंगी;

(xiv) संस्था के संकाय अधिष्ठाता (डीन फैकलटी ऑफ इन्स्टीच्यूशन्ज)/विभागाध्यक्षों से, छात्रों के अभ्यावेदन (नामांकन) के विषय में, परीक्षा संचालन और छात्रों और शिक्षकों से सम्बन्धित अन्य विवादिकों पर सम्पर्क बनाए रखना;

(xv) कुलपति के सीधे अधीक्षण और निदेश के अधीन कार्य करना;

(xvi) परीक्षा परुपों (इंग्जामिनेशन फॉर्मज) को प्राप्त करना और विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र (अडमिट कार्ड) जारी करना;

(xvii) कर्मचारिवृन्द (स्टाफ), परीक्षकों, पर्यवेक्षण कार्य, अधीक्षण तथा परीक्षाओं के संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन/पर्नुमूल्यांकन तथा परीक्षा परिणामों के सारणीयन/घोषणा/प्रकाशन के लिए नियुक्त अन्य कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) की बाबत विभिन्न यात्रा भत्तों/दैनिक भत्तों के बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करना तथा मंजूर करना; और

(xviii) कुलपति और कुलाधिपति द्वारा उसे समय-समय पर आबन्दित किसी अन्य कर्तव्य या कृत्य का पालन करना।

(4) कुलपति, परीक्षा नियन्त्रक की अनुपस्थिति में उसकी किन्हीं या समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा।

10. छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्टयूडेन्ट्स वेलफेयर) की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य.—(1) कुलपति द्वारा, चयन समिति, जिसकी अध्यक्षता कुलपति करेगा, की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से या जो किसी अन्य विश्वविद्यालय का शिक्षक रहा हो या किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति में से जो आचार्य की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा या समतुल्य अनुभव वाले में से

छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्ट्र्यूडेंट्स वेलफेयर) नियुक्त किया जाएगा। वह कुलपति को रिपोर्ट करेगा।

(2) छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्ट्र्यूडेंट्स वेलफेयर) की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जो विश्वविद्यालय के पश्चात् वर्ती परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्ट्र्यूडेंट्स वेलफेयर) कुलपति के अनुमोदन से, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

- (i) विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में छात्र निवास का प्रबन्ध करना और विश्वविद्यालय की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों के अनुशासन का पर्यवेक्षण करना;
- (ii) विश्वविद्यालय परिसर (केम्पस) में छात्रों के पाठ्यक्रम के साथ की और सांस्कृतिक गतिविधियों को योजनाबद्ध आयोजित करना और उनका पर्यवेक्षण करना;
- (iii) विश्वविद्यालय परिसर (केम्पस) में छात्रों के शारीरिक कल्याण की और एन०सी०सी० तथा एन०एस०एस० गतिविधियों की देखरेख करना;
- (iv) विश्वविद्यालय के छात्रों में परिसर (केम्पस) में के और से बाहर के अनुशासन के सम्बन्धित समस्त मामले सिवाय उन मामलों के जो शैक्षणिक कार्य से सम्बन्धित हैं जिन्हें विभागाध्यक्षों, और/या अध्ययन अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्टडीज) द्वारा निपटाए जाएंगे, को निपटाना और सम्यक् जांच के पश्चात् ऐसी शास्त्रियां अधिरोपित करना जो आवश्यक समझी जाएं;
- (v) विश्वविद्यालय के छात्रों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए अर्थोपाय करना—सामाजिक, नैतिक तथा भावनात्मक मूल्य उनके मन में बैठाना, महान विचारों, जैसे कि देश के प्रति वफादारी, कर्तव्यनिष्ठा और सच्चाई का अनुसरण तथा अध्ययन और अन्य पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों तथा खेल-कूद (स्पोर्ट्स) आदि में उत्कृष्टता प्राप्त कराना;
- (vi) छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्ट्र्यूडेंट्स वेलफेयर) के कार्यालय पर सम्पूर्ण नियन्त्रण और पर्यवेक्षण रखना;
- (vii) कुलपति द्वारा समय-समय पर उसे आवंटित किसी अन्य कर्तव्य या कृत्य का पालन करना।

(4) कुलपति, छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्ट्र्यूडेंट्स वेलफेयर) की अनुपस्थिति में उसके किन्हीं या समस्त कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा।

11. स्नातकोत्तर अध्ययन अधिष्ठाता (डीन ऑफ पोस्टग्रेजुएट) की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसके कृत्य.—(1) स्नातकोत्तर अध्ययन अधिष्ठाता (डीन ऑफ पोस्टग्रेजुएट स्टडीज) कुलपति द्वारा, विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से या जो किसी अन्य विश्वविद्यालय का शिक्षक रहा हो जो आचार्य की पंक्ति से नीचे के या समतुल्य अनुसंधान तथा उद्योग अर्हता से नीचे का न हो, कुलपति की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों, जिसकी पुष्टि कुलाधिपति द्वारा की जाएगी, पर नियुक्त किया जाएगा।

(2) स्नातकोत्तर अध्ययन अधिष्ठाता (डीन ऑफ पोस्टग्रेजुएट स्टडीज) की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जो विश्वविद्यालय के पश्चात् वर्ती परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) स्नातकोत्तर अध्ययन अधिष्ठाता (डीन ऑफ पोस्टग्रेजुएट स्टडीज) कुलपति के अनुमोदन से निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करेगा और कुलपति को सीधे रिपोर्ट करेगा :—

- (i) विश्वविद्यालय के संकाय/विद्यालय/महाविद्यालयों तथा विभागों में स्नातकोत्तर अध्ययन अनुसंधान का आयोजन और समन्वयन तथा संचालन करना;

(ii) विश्वविद्यालय स्तर पर अपने-अपने संकाय अधिष्ठाताओं (डीन ऑफ फैकल्टीज) और अध्ययन अधिष्ठाताओं (डीन ऑफ स्टडीज) के माध्यम से समस्त शैक्षणिक क्रियाकलापों का समन्वयन करना;

(iii) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों के अध्यापन कर्मचारिवृन्द (टीचिंग स्टाफ) के कार्य का जब कभी आवश्यक हो, समन्वयन करना परन्तु संकाय अधिष्ठाताओं (डीन ऑफ फैकल्टीज) अध्ययन अधिष्ठाताओं (डीन ऑफ स्टडीज) और विभागाध्यक्षों के उनके अपने-अपने विभागों के कार्य में प्रत्यक्षतः नियन्त्रण न करना;

(iv) संकाय/विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थाओं/विभागों में अनुसंधान मानकों को विकसित करने और उनमें सुधार लाने के लिए शैक्षणिक मार्गदर्शक (अकैडमिक गाइड) के रूप में कार्य करना;

(v) विभिन्न शैक्षणिक प्रक्रियाओं और प्रणालियों की कृत्यशीलता में नवीनतम प्रौद्योगिकी (टैक्नोलोजीज) और विचार (आइडियाज) लाने की दृष्टि से नवीनीकरण और नए विचारों का सुझाव देना तथा प्रस्तावित करना; और

(vi) कुलपति और या कुलाधिपति द्वारा समय-समय पर उसे आबन्दित किसी अन्य कर्तव्य या कृत्य का पालन करना।

(4) स्नातकोत्तर अध्ययन अधिष्ठाता (डीन ऑफ पोस्टग्रेजुएट स्टडीज) की अनुपस्थिति में उसकी किन्हीं या समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कुलपति विश्वविद्यालय केव्र किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा।

12. पुस्तकालयाध्यक्ष।—(1) कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन पुस्तकालयाध्यक्ष को, प्रयोजन के लिए कुलाधिपति द्वारा गठित चयन समिति, जिसकी अधिकारी कुलपति द्वारा की जाएगी, की सिफारिशों पर कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष कुलपति के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा तथा विश्वविद्यालय के सभी पुस्तकालयों के रख-रखाव और उनकी सेवाओं की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के कुलपति द्वारा यथा अनुमोदित कर्तव्य होंगे, अर्थात्:—

(क) वह विश्वविद्यालय के पुस्तकालय और पुस्तकालय कार्मिकों तथा विभागों के पुस्तकालयों या संग्रहों का साधारण समग्र पर्यवेक्षण करेगा;

(ख) वह विभाग के संग्रहों सहित विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय बजट तैयार करेगा;

(ग) वह पुस्तकालय की सभी सामग्रियों के प्राप्त करने और उन्हें चढ़ाने (सम्मिलित करने) का उत्तरदायी होगा;

(घ) वह समस्त पुस्तकालय सामग्रियों के क्रय मांग पत्र (अध्येक्षा) को तैयार करने (सूत्रपात करने) के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङ) वह जर्नलों के अभिदान का समय पर नवीकरण करवाने का उत्तरदायी होगा;

(च) वह मासिक अन्तरालों पर पुस्तकालय न्यूज लैटर तैयार करेगा जिसमें अन्तिम पर्वती न्यूज लैटर से प्राप्त समस्त पुस्तकालय सामग्रियों और छात्रों और कर्मचारिवृन्द के हित के समयबद्ध पुस्तकालय समाचार (लाइब्रेरी न्यूज) की सूची होगी;

(छ) वह छात्रों और कर्मचारिवृन्द द्वारा पुस्तकालय के प्रयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए बनाए गए प्रोग्राम का सूत्रपात करेगा, उसमें भाग लेगा और सहयोग प्रदान करेगा;

(ज) वह कूलपति के अनुमोदन से पुस्तकालय के समय की इस प्रकार व्यवस्था करेगा ताकि छात्रों और संकाय सदस्यों दोनों द्वारा पुस्तकालय का अधिकतम प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके; और

(झ) वह विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित विभागों और अन्य अनुसंधान केन्द्रों, संकाय/विद्यालय/महाविद्यालयों और संस्थाओं के लिए ऐसे वॉल्यूमज और जर्नलों के लघु संग्रहणों की व्यवस्था करेगा जिनका संकाय और स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा सन्दर्भ (रैफरनसीज) के रूप में प्रायः निरन्तर प्रयोग होता रहे।

13. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण।—धारा 17 में विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे अर्थात्:—

- (i) योजना बोर्ड;
- (ii) वित्त समिति;
- (iii) विश्वविद्यालय विकास समिति; और
- (iv) पूर्व छात्र (ऐलुमिनी) सम्बन्ध समिति।

14. शासी निकाय के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि।—(1) धारा 18 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शासी निकाय के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(2) यदि खण्ड (1) के अधीन कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य, सदस्य नहीं रहता है तो अतिशेष अवधि के लिए नया सदस्य नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य की अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् शासी निकाय के सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(4) बैठक में समस्त विनिश्चय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा लिए जाएंगे मतों की बराबरी की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक और द्वितीय मत होगा।

15. शासी निकाय की शक्तियां और कृत्य।—धारा 18 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अतिरिक्त, शासी निकाय की निम्नलिखित अतिरिक्त शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

- (i) धारा 27 के अधीन बनाए जाने वाले पश्चात्वर्ती परिनियमों और धारा 27 के अनुसार उनके संशोधनों और प्रबन्ध बोर्ड द्वारा धारा 28 के अधीन बनाए जाने वाले प्रथम अध्यादेशों और उनके संशोधनों और धारा 29 के अधीन बनाए जाने वाले पश्चात्वर्ती अध्यादेशों तथा उनके संशोधनों को अनुमोदित करना;
- (ii) विश्वविद्यालय की पुस्तकालय/प्रयोगशालाएं संस्थापित करना, सज्जित करना और बनाए रखना;
- (iii) विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें वह आवश्यक समझे, में ज्ञान के अनुसंधान और अभिवृद्धि तथा प्रसार की व्यवस्था करना; और
- (iv) विश्वविद्यालय के उद्देशयों की प्राप्ति के लिए समस्त ऐसे उपाय करना और कृत्य करना जो वांछनीय हो।

16. प्रबन्ध बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि।—(1) धारा 19 के खण्ड (ख), (ग) और (घ) के अधीन प्रबन्ध बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(2) यदि खण्ड (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य सदस्य नहीं रह जाता है तो शेष अवधि के लिए नया सदस्य नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्य अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(4) बैठक (अधिवेशन) में सभी विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा लिए जाएंगे। मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(5) अविनिश्चित मामलों के विनिश्चय के लिए कुलाधिपति को अग्रेषित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

17. प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।—धारा 19 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन प्रबन्ध बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(1) प्रबन्ध बोर्ड को, कुलाधिपति के नियन्त्रण के अध्यधीन विश्वविद्यालय की आमदनी (रेवेन्यू) तथा सम्पत्ति के प्रबन्धन और प्रशासन तथा विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासनिक क्रियाकलापों के संचालन, जिनके बारे में अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है, की शक्ति होगी।

(2) अधिनियम, पश्चात्वर्ती परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अध्यधीन, प्रबन्ध बोर्ड की उसमें निहित अन्य शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

- (i) अध्यापन और अन्य शैक्षणिक पद अनुमोदित करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित आचार्यों, रीडरों प्राध्यापकों तथा अन्य शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के कृत्यों तथा सेवा की शर्तों को परिभाषित करना;
- (ii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखों, विनिधानों, सम्पत्ति तथा विश्वविद्यालय के सभी अन्य कार्यकलापों का प्रबन्धन और विनियमन करना और उतने अभिकर्त्ताओं को नियुक्त करना जितने उचित समझे जाएं;
- (iii) विश्वविद्यालय के धन को, किसी अनुपयोजित आय सहित, ऐसे स्टॉकों, निधियों, शेरों या प्रतिभूतियों में विनिहित करना, जैसा वह ठीक समझे या भारत में स्थावर सम्पत्ति के क्रय में विनिहित करना जिसमें ऐसे विनिधानों में समय-समय पर परिवर्तन करने की ऐसी शक्ति है, परन्तु इस खण्ड के अधीन वित्त समिति से परामर्श किए बिना कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी;
- (iv) प्रशासनिक, अनुसंचिवीय (लिपिकीय) और अन्य आवश्यक पदों का सृजन, विद्या परिषद् तथा वित्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर करना और उसके लिए नियुक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करना;
- (v) कर्मचारियों में, पश्चात्वर्ती परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना;
- (vi) विश्वविद्यालय की ओर से किसी स्थावर (अचल) सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरणों को स्वीकार करना;

(vii) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और छात्रों की जो किसी कारण से व्यक्ति अनुभव करे, शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना या उन्हें दूर करना;

(viii) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा के उपयोग की व्यवस्था करना;

(ix) अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति को विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी या प्राधिकरण (अर्थात् टी) को या इस द्वारा नियुक्त किसी समिति को, जैसा वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित करना;

(3) प्रबन्ध बोर्ड एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा जिसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा—

(i) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन;

(ii) प्राप्तियों और वितरणों की रकमें और प्रयोजन जिसके लिए ये किए गए थे;

(iii) अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और प्रत्येक की स्थिति और पारिश्रमिक, विभिन्न सेवानां और कक्षाओं में छात्रों की संख्या और प्रत्येक में अनुसरण किए गए शिक्षा के पाठ्यक्रम; और

(iv) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए व्ययों का प्रावकलन ।

18. विद्या परिषद् का गठन.—(1) विद्या परिषद् का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से होगा, अर्थात्—

(क) पदेन सदस्यः—

(i) कुलपति (अध्यक्ष);

(ii) विश्वविद्यालय का संकाय अधिष्ठाता (डीनज ऑफ फैकल्टीज);

(iii) अध्ययन अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्टडीज);

(iv) रजिस्ट्रार (सदस्य सचिव);

(v) परीक्षा नियन्त्रक;

(vi) छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्ट्यूडेंट्स वेलफेयर)

(vii) दूरवर्ती शिक्षा अधिष्ठाता (डीन ऑफ डिस्टॅन्स एजुकेशन)

(viii) स्नातकोत्तर अध्ययन अधिष्ठाता (डीन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज);

(ix) सहकारी अध्ययन तथा नियोजन अधिष्ठाता (डीन ऑफ कोऑपरेटिव स्टडीज एण्ड प्लेसमेंट);

(x) पुस्ताकालाध्यक्ष; और

(xi) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्थाओं के निदेशक ।

(ख) अन्य सदस्यः—

- (i) दो सदस्य, जो विद्या परिषद् द्वारा उनके विशेष ज्ञान के कारण सहयोजित किए गए हों और जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों;
- (ii) रजिस्ट्रार विद्या परिषद् का सदस्य सचिव होगा तथा उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।
- (iii) सदस्यों के एक तिहाई से गणपूर्ति होगी;
- (iv) पदेन सदस्यों से अन्यथा विद्या परिषद् के सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;
- (v) बैठक (अधिवेशन) में सभी विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा लिए जाएंगे। बैठक का अध्यक्ष का, मतों के बराबर होने की दशा में निर्णायक मत होगा; और
- (vi) अविनिश्चत मामलों को कुलाधिपति को अग्रेषित किया जाएगा और कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

19. विद्या परिषद् की शक्तियां और कर्तव्यः—(1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होने के नाते अधीक्षण करेगी, निदेश देगी और नियन्त्रण रखेगी तथा शिक्षण, शिक्षा और परीक्षाओं के स्तरों को बनाए रखने तथा उपाधियों को अभिप्राप्त करने से सम्बन्धित अन्य विषयों के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और कर्तव्यों का पालन करेगी जो पश्चात्वर्ती परिनियमों विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अधिनियम, पश्चात्वर्ती परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अध्यधीन विद्या परिषद् को उसमें निहित समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी और उसके निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात्—

- (क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक पॉलिसियों (नीतियों) पर साधारण पर्यवेक्षण रखना और शिक्षण के तरीकों, संकाय/विद्यालय/महाविद्यालयों में सहकारी (कम्बाइंड) अध्यापन, अनुसंधान मूल्यांकन या शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में निदेश देना;
- (ख) अन्तर—संकाय आधार पर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए समितियों की स्थापना या नियुक्ति करने हेतु अन्तर—संकाय समन्वय करना;
- (ग) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी संकाय या प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निर्देशित किए जाने पर विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना;
- (घ) पश्चात्वर्ती परिनियमों और अध्यादेशों के अनुकूल विनियम बनाना जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों और अध्ययनवृत्तियों को दिए जाने, फीस रियायतों और उपस्थिति आदि के सम्बन्ध में हो;
- (ङ) प्रबन्ध बोर्ड को निम्नलिखित की बाबत नए अध्यादेशों के प्रारूप या विद्यमान अध्यादेशों के संशोधन प्रारूप की संस्तुति (सिफारिश) करना:—
 - (i) शिक्षक की अहताएं;
 - (ii) विश्वविद्यालय/संकाय/विद्यालय/महाविद्यालय के कार्यकलापों में छात्रों की सहभागिता और नियन्त्रण (गवरनैन्स);

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा संस्थापित या अनुरक्षित संकाय/विद्यालय/ महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं का प्रबन्धन;

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाण—पत्र अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं, इनके लिए अहताएं, अध्ययन के पाठ्यक्रमों की अवधि तथा ऐसी पाठ्यक्रमों की अन्य आवश्यक विशेषताएं और ऐसी उपाधियां, डिप्लोमां या प्रमाण—पत्रों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं के लिए परीक्षाओं का प्रकार और प्रकृति;

(v) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा कर्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;

(vi) विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रवेश और उनका अभ्यावेशन (इन्सोलमैन्ट); छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना; छात्रों के निवास की बाबत शर्तें;

(vii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं (स्टाइपन्ड), पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(viii) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रवेश हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस;

(ix) परीक्षकों, अनुसीमकों (मॉडरेटरज) और सारणीकारों (टेबुलेटरज) आदि को सन्दर्भ किया जाने वाला पारिश्रमिक;

(x) अन्य निकायों, समितियों या बोर्डों का सृजन, संरचना और कृत्य जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक या वॉलनीय हों;

(xi) छात्राओं के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए विशेष प्रबन्ध (व्यवस्थाएं), यदि कोई हों, करना;

(xii) कुलाधिपति को किसी विशिष्ट संकाय/संकायों में नए विषय (विषयों) को आरम्भ करने या नए विभाग (विभागों)/संस्था (संस्थाओं)/स्कूल (स्कूलों) अध्ययन केन्द्र (केन्द्रों) को खोलने की सिफारिश करना। तथापि विद्या परिषद् मामले (विषय) में प्रबन्ध बोर्ड को अन्तिम रूप से सिफारिश करने से पूर्व विद्यमान संकाय/संकायों के कार्य का मूल्यांकन करेगी।

परन्तु यदि प्रबन्ध बोर्ड विद्या परिषद् से असहमत होता है तो यह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो—तिहाई बहुमत द्वारा प्रारूप को संशोधित रूप से स्वीकार (अंगीकार) कर सकेगा या इसे नामंजूर कर सकेगा और यदि दो—तिहाई सदस्यों का बहुमत नहीं है तो मामले (विषय) को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट अहर्ताओं के अध्यधीन शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की संख्या, अहताएं और अन्य पात्रता शर्तों को विहित करना;

(ii) शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की अस्थाई रिक्तियों के लिए नियुक्ति की रीति विनिर्दिष्ट करना;

(iii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों (एमिरिटस), अध्येताओं (फैलोज), कलाकारों तथा लेखकों की नियुक्ति के लिए उपबन्ध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबन्धनों और शर्तों का अवधारण करना;

(iv) कोर्स पाठ्यक्रम लेखकों (कोर्स साइटरों), काउनसलरों, परीक्षकों और निरीक्षकों इन्विजिलेटरज) को संदेय पारिश्रमिक और संदेय यात्रा तथा अन्य भूतों को वित्त समिति से परामर्श करने के पश्चात् नियत करना; और

(v) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां और अध्ययनवृत्तियां संस्थित करना।

20. विद्या परिषद् की बैठकें (अधिवेशन).—(1) विद्या परिषद् की बैठक ऐसी तारीख को और ऐसे समय पर या ऐसे स्थान पर होगी जो कुलपति द्वारा नियत किया जाए।

(2) बैठक (अधिवेशन) की कार्यसूची की प्रतियां सदस्यों को बैठक से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व दी जाएंगी।

(3) विद्या परिषद् की बैठकों की गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों के एक-तिहाई से होगी।

(4) विद्या परिषद् की बैठक में विचार में लाए जाने वाले समस्त प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। विद्या परिषद् के अध्यक्ष को प्रश्न पर मत देने का अधिकार होगा और मतों की बराबरी होने की दशा में अध्यक्ष को द्वितीय और निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

21. योजना बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य.—(1) योजना बोर्ड कुलपति तथा कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले अधिक से अधिक छह सदस्यों से गठित होगा।

(2) कुलपति से अन्यथा, योजना बोर्ड के सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(3) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के विकास और विस्तार के लिए समुचित योजनाएं परिकल्पित करेगा और बनाएगा और इसके अतिरिक्त इसके पास कुलाधिपति, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् को किसी भी विषय पर परामर्श देने का अधिकार होगा जिसे यह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे।

(4) योजना बोर्ड ऐसी समितियों का गठन कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों की योजना और उनकी निगरानी (मॉनीटरिंग) के लिए आवश्यक हों।

(5) योजना बोर्ड ऐसे अन्तरालों पर बैठक (अधिवेशन) करेगा जैसा वह समीचीन समझे, परन्तु यह एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें करेगा।

(6) कुलपति योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(7) विनिश्चय बहुमत द्वारा लिया जाएगा। बराबरी की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

22. वित्त समिति की शक्तियां और कर्तव्य.—(1) वित्त समिति निम्नलिखित से गठित होगी, अर्थात्—

(क) कुलपति;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी से अन्यथा, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से नियुक्त किया जाने वाला एक व्यक्ति; और

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति।

(2) कुलपति वित्त समिति का अध्यक्ष होगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी वित्त समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा और उसे मत देने का अधिकार होगा।

(4) पदेन सदस्य से अन्यथा वित्त समिति के सभी सदस्य, उस तारीख से जिसको वह समिति के सदस्य बनते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(5) वित्त समिति के तीन सदस्यों से समिति की बैठक की गणपूर्ति होगी।

(6) वित्त समिति लेखों का परीक्षण करने तथा व्ययों के प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए वर्ष में कम से कम तीन बैठकें करेगी:

परन्तु दो क्रमवर्ती बैठकों के मध्य एक सौ अस्सी दिनों से अनधिक की अवधि व्यपगत होगी।

(7) ग्रेडों के संशोधन (पुनरीक्षण), वेतनमानों को अपग्रेड करने और उन मदों, जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, सम्बन्धित समस्त प्रस्तावों का परीक्षण, उन पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा किया जाएगा।

(8) वित्त समिति वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्ययों के लिए सीमाओं को नियत करेगी जो विश्वविद्यालय की आय और उसके साधनों पर आधारित होगी, और विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार नियत सीमाओं से अधिक व्यय, वित्त समिति के अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जाएगा।

(9) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्रावक्कलन वित्त समिति के समक्ष विचार और टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् संशोधनों सहित या संशोधनों के बिना समिति द्वारा नियत की गई कुल (समस्त) सीमा सहित प्रबन्ध बोर्ड को प्रस्तुत किए जाएंगे।

23. संकाय।—(1) विश्वविद्यालय के ऐसे संकाय होंगे जो पश्चात्वर्ती परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) प्रत्येक संकाय में ऐसे महाविद्यालय/विद्यालय/अध्ययन के विभाग होंगे जो इसे अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

(3) कोई भी विभाग पश्चात्वर्ती परिनियमों के सिवाय स्थापित या समाप्त नहीं किया जाएगा।

24. प्राधिकरणों की बाबत प्रकीर्ण उपबन्ध।—(1) अन्य समितियां—शासी निकाय या विद्या परिषद् ऐसे बोर्ड या समितियां नियुक्त कर सकेंगी जो ऐसी नियुक्ति करने वाले शासी निकाय या विद्या परिषद् के सदस्यों से गठित होंगी, ऐसे अन्य व्यक्ति भी नियुक्त किए जा सकेंगे, जिन्हें ऐसा प्राधिकरण (अर्थात् एसा प्राधिकरण) प्रत्येक मामले में उचित समझे; और ऐसा कोई बोर्ड या समिति उसे सौंपे गए ऐसे किसी विषय को, उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकरण द्वारा पश्चात्वर्ती पुष्टि के अध्यधीन, निपटा सकेगा।

(2) निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता करना जहां परिनियमों में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है।—जहां अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अध्यक्ष के लिए विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, बोर्ड या समिति की बैठक की अध्यक्षता करने हेतु कोई उपबन्ध नहीं किया गया है या अध्यक्ष, जहां इस प्रकार व्यवस्था की गई है, अनुपस्थित है, तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे।

(3) त्यागपत्र।—(i) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, रजिस्ट्रार को सम्बोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा और त्यागपत्र रजिस्ट्रार द्वारा पत्र प्राप्त करते ही प्रभावी हो जाएगा।

(ii) विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी (वैतनिक हो या अन्यथा) रजिस्ट्रार को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा:

परन्तु ऐसा त्यागपत्र उसी तारीख को प्रभावी होगा जिसको कि रिक्ति को भरने के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा इसे स्वीकार किया गया हो।

(iii) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकरण का कोई भी सदस्य उस निकाय का सदस्य नहीं रहता है जिससे वह चुना (निर्वाचित) या नियुक्त किया गया है तो वह उस प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहेगा।

25. अध्यापन पदों पर नियुक्तियां और उनसे हटाए जाने की रीति।—(1) विश्वविद्यालय के शिक्षक कुलाधिपति के अनुमोदन से चयन समिति की सिफारिशों पर कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(2) विद्या परिषद्, उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो—तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा शिक्षक की मान्यता वापिस ले सकेगी:

परन्तु ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उस शिक्षक को ऐसे समय के भीतर, जो उस नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने का लिखित नोटिस न दे दिया जाए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित किया जाए और जब तक विद्या परिषद् द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, और किसी साक्ष्य पर, जो वह उसके समर्थन में पेश करे, विचार न कर लिया जाए।

(3) किसी भी व्यक्ति को, प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों के सिवाय, विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा या उसे मान्यता नहीं दी जाएगी।

(4) कुलपति एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए आवश्यकता पर आधारित तदर्थ/संविदात्मक नियुक्तियां करने के लिए प्राधिकृत होगा।

26. चयन समिति।—(1) आचार्य, रीडर (सह—आचार्य), सहायक आचार्य, प्राध्यापक, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक, वित्त अधिकारी और पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर नियुक्तियों के लिए सिफारिशों करने हेतु एक चयन समिति होगी।

(2) ऐसी प्रत्येक चयन समिति कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा, और कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति (व्यक्तियों) से गठित होगी और इसके अतिरिक्त चयन समिति के, नीचे सारणी के स्तम्भ (ii) में विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्त हेतु सिफारिशें करने के लिए तथाकथित सारणी के स्तम्भ (i) की तत्त्वानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, सदस्य होंगे:—

आचार्य/रीडर (सह आचार्य)।—(i) सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष, यदि वह आचार्य हो।

(ii) दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हों, कुलाधिपति द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी सिफारिश कुलपति द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्य सम्बन्धित होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।

सहायक आचार्य/प्राध्यापक।—(i) सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष।

(ii) दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हों, कुलाधिपति द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश कुलपति द्वारा उस विषय में, जिससे सहायक आचार्य या प्राध्यापक सम्बन्धित होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।

रजिस्ट्रार/परीक्षा नियन्त्रक/मुख्यवित्त और लेखा अधिकारी।—तीन व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट हों। इनमें से एक सदस्य क्रमशः शैक्षणिक प्रशासन, प्रबन्धन और वित्त में विशेषज्ञ होना चाहिए।

पुस्तकालयाध्यक्ष।—दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों, जिन्हें विशेष या पुस्तकालय विज्ञान का विशेष ज्ञान हो, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) विश्वविद्यालय के आचार्यों, रीडर (सह आचार्य), प्राध्यापकों या प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति और प्रोन्ति के सम्बन्ध में चयन समिति की सिफारिशों, यथास्थिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य विनियामक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों के अध्यधीन होंगी।

27. गैर अध्यापन पदों पर नियुक्तियों के लिए रीति।—(1) गैर अध्यापन पदों के लिए सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा निम्नलिखित से गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी—

- (i) कुलपति (अध्यक्ष);
- (ii) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य; और
- (iii) रजिस्ट्रार, सदस्य सचिव।

(2) समिति का सदस्य सचिव इसकी कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएं।

28. अध्यापन पदों की सेवा के निबन्धन और शर्तें।—(1) विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द, तत्प्रतिकूल करार के अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा तत्पश्चात् बनाए गए परिनियमों में यथाविनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों द्वारा शासित होंगे।

(2) शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की उपलब्धियां ऐसी होंगी जो विश्वविद्यालय द्वारा तत्पश्चात् बनाए गए परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य लिखित संविदा पर नियुक्त किए जाएंगे जिसके लिए प्ररूप विश्वविद्यालय द्वारा तत्पश्चात् बनाए गए परिनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) खण्ड (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति रजिस्ट्रार के पास जमा करवाई जाएगी।

(5) विश्वविद्यालय और (1) में वर्णित व्यक्तियों के बीच किसी संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद सम्बन्धित शिक्षक या अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध (प्रेरणा) पर अथवा विश्वविद्यालय के अनुरोध (प्रेरणा) पर नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित अधिकारी या शिक्षक या कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त अधिनिर्णयक से गठित समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा और समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।

29. शिक्षकों का हटाया जाना।—(1) जहां किसी शिक्षक के विरुद्ध अवचार का आरोप (अभिकथन) है, वहां कुलपति, यदि उचित समझे लिखित आदेश द्वारा शिक्षक को निलम्बित करेगा और कुलाधिपति को तत्काल उन परिस्थितियों की रिपोर्ट देगा जिनके अधीन आदेश किया गया था:

परन्तु कुलाधिपति की यह राय है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं जो शिक्षक के निलम्बन को समर्थित नहीं करती हैं तो वह उस आदेश को प्रतिसंहृत करेगा।

(2) कुलाधिपति, अवचार के आधार पर शिक्षक को, उसकी सेवा की संविदा या नियुक्ति के निबन्धनों में किसी बात के होते हुए भी, हटाने का हकदार होगा।

(3) जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय कुलाधिपति उचित और पर्याप्त कारण के और लिखित में तीन मास का नोटिस देने या नोटिस के बदले में तीन मास के वेतन का संदाय करने के सिवाय किसी शिक्षक को हटाने का हकदार नहीं होगा।

(4) किसी भी शिक्षक को उपखण्ड (2) या उपखण्ड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसके बारे में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध उसे कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

(5) शिक्षक का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको उसके हटाए जाने का आदेश किया गया है:

परन्तु जहां कोई शिक्षक उसके हटाए जाने के समय निलम्बित है तो उस दशा में उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि उसे निलम्बित किया गया था।

(6) इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी शिक्षक, कुलपति को लिखित में तीन मास का नोटिस देकर त्यागपत्र देने का हकदार होगा।

30. गैर अध्यापन पदों की सेवा के निबन्धन और शर्तें—(1) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द से अन्यथा विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा तत्पश्चात् बनाए गए परिनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सेवा के निबन्धनों और शर्तों द्वारा शासित होंगे।

(2) शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द से अन्यथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति तथा उपलब्धियां ऐसी होंगी जो विश्वविद्यालय द्वारा तत्पश्चात् बनाए गए परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

31. शिक्षक से भिन्न कर्मचारियों का हटाया जाना—(1) शिक्षक से भिन्न विश्वविद्यालय के कर्मचारी को, उसकी सेवा की संविदा या उसकी नियुक्ति के निबन्धनों में से किसी बात के होते हुए भी, उस प्राधिकरण द्वारा हटाया जा सकेगा, जो उस कर्मचारी को नियुक्त करने में सक्षम है, यदि उसने धारा 22 के अधीन कोई निर्हता उपगत कर ली है।—

- (क) वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है;
- (ख) वह अनुन्मोदित दिवालिया है;
- (ग) वह किसी दाण्डक अपराध या नैतिक अधमता से ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है; और
- (घ) वह अन्यथा साबित अवचार का दोषी है :

परन्तु किसी भी कर्मचारी को कुलाधिपति के अनुमोदन के बिना हटाया नहीं जाएगा।

(2) किसी भी ऐसे कर्मचारी को खण्ड (1) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसके बारे में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

(3) जहां ऐसे कर्मचारी का हटाया जाना खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट से भिन्न कारणों से है तो वहां उसे लिखित में तीन मास का नोटिस दिया जाएगा या नोटिस के बदले में तीन मास का वेतन संदर्भ किया जाएगा परन्तु यदि कर्मचारी स्थायी नियमित कर्मचारी है। उस कर्मचारी की दशा में जो परिवीक्षा पर है केवल एक मास का नोटिस अपेक्षित होगा।

(4) इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षक से भिन्न कर्मचारी निम्नलिखित दशाओं में त्यागपत्र देने का हकदार होगा,—

- (i) स्थायी कर्मचारी की दशा में नियुक्त करने वाले प्राधिकरण को लिखित में तीन मास का नोटिस देने के पश्चात् या विश्वविद्यालय को उसके बदले में तीन मास का वेतन संदर्भ करके;

(ii) किसी अन्य मामले में नियुक्त करने वाले प्राधिकरण को लिखित में एक मास का नोटिस देकर या विश्वविद्यालय को उसके बदले में एक मास का वेतन संदर्भ करके।

32. कर्मचारियों की आचार संहिता।—(1) प्रत्येक कर्मचारी सभी समयों पर कर्तव्य के प्रति पूर्ण सत्यनिष्ठा और परायणता बनाए रखेगा और अपने पदीय कामकाज (ऑफिशियल डीलिंगज) में सर्वथा ईमानदार और निष्पक्ष रहेगा।

(2) कर्मचारी, स्टाफ के अन्य सदस्यों, छात्रों और आम जनता के साथ व्यवहार में सभी समयों पर शिष्ट रहेगा।

(3) नियुक्ति के निबन्धनों में जब तक विनिर्दिष्टतः अन्यथा उपबन्धित न हो, प्रत्येक कर्मचारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और उसे अनुसूचित कामकाज के घंटों और अवकाश तथा प्रावकाश के दिनों पर ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जा सकेगा जो उसे सम्बद्ध प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा सौंपे जाएं। इन कर्तव्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ उन समितियों, जिनके लिए विश्वविद्यालय उसे नियुक्त करे, की बैठकों में उपस्थिति भी होगी।

(4) कर्मचारी से कामकाज के अनुसूचित घण्टों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाएगी जिनके दौरान उसका अपने कर्तव्य के स्थान पर उपस्थित रहना अपेक्षित होगा।

(5) विधिमान्य कारणों और या अकलिप्त आपातिक कारणों के सिवाय कोई भी कर्मचारी पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

(6) कोई भी कर्मचारी, छुट्टी या प्रावकाश के दौरान भी, समुचित प्राधिकारी (अथॉरिटी) की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना स्थान नहीं छोड़ेगा।

(7) जब भी स्थान को छोड़ना हो तो, कर्मचारी उस विभागाध्यक्ष को, जिसके साथ वह कार्यरत है, यदि वह स्वयं विभागाध्यक्ष है तो अध्ययन अधिष्ठाता (डीन ऑफ फैकल्टी) को अपना वह पता सूचित करेगा जिस पर वह स्थान से अपनी अनुपस्थिति अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा।

(8) कोई भी कर्मचारी विश्वविद्यालय के परिसर (कैम्पस) में राजनैतिक गतिविधियों में सक्रिय भाग नहीं लेगा या अपनी पदीय हैसियत का अनुचित लाभ नहीं उठाएगा या विश्वविद्यालय प्रसुविधाओं के राजनैतिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग की अनुज्ञा देगा।

(9) कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रसारण में अनाम से या अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में या प्रैस के लिए किसी संसूचना (कम्यूनीकेशन) में या किसी लोक कथन (पब्लिक अटरेंस), तथ्य या राय की बाबत कोई ऐसा कथन (स्टेटमैन्ट) नहीं करेगा:

- (i) जिससे विश्वविद्यालय की किसी नीति (पॉलिसी) या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना हो; या
- (ii) जो विश्वविद्यालय और केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था या संगठन या लोक सदस्यों (मैम्बरज ऑफ पब्लिक) के बीच सम्बन्धों को परेशानी में डाल दे; या
- (iii) जो विश्वविद्यालय के नाम या उसमें उसकी हैसियत का सम्प्रयोजन करे; और
- (iv) इस पैरा की कोई भी बात किसी कर्मचारी द्वारा उसकी पदीय हैसियत में (ऑफिशयल कैपेसिटी) या उसे सौंपे गए कर्तव्यों के सम्बन्ध में अभिव्यक्ति किसी कथन या मत के लिए लागू नहीं होगी।

(10) इस पैरा के उप-पैरा (ग) (iii) में यथा उपबन्धित के सिवाय:—

- (क) कोई भी कर्मचारी, सम्बद्ध प्राधिकरण (अथॉरिटी) की पूर्व मंजूरी के सिवाय किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा संचालित किसी जांच के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं देगा।

(ख) जहां उप-पैरा (ग) (i) के अधीन कोई मंजूरी प्रदान की गई है तो ऐसा साक्ष्य देने वाला कोई भी कर्मचारी विश्वविद्यालय या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति (पॉलिसी) या किसी कार्रवाई की आलोचना नहीं करेगा।

(ग) इस पैरा की कोई भी बात:—

- (i) विश्वविद्यालय द्वारा, संसद द्वारा या किसी राज्य विधानमण्डल द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी (अथॉरिटी) के समक्ष किसी जांच में दिए गए किसी साक्ष्य के लिए; या,
- (ii) किसी न्यायिक जांच में दिए गए साक्ष्य के लिए; या
- (iii) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों (अथॉरिटीज) द्वारा आदेशित किसी विभागीय जांच में दिए गए किसी साक्ष्य के लिए लागू नहीं होगी।

(11) कोई भी कर्मचारी, सम्बद्ध प्राधिकरण (अथॉरिटी) के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसार के सिवाय या उसे सौंपे गए कर्तव्यों के सद्भाव में अनुपालन के सिवाय किसी पदीय दस्तावेज (ऑफिशियल डाक्यूमेंट) या सूचना को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यक्ति को नहीं देगा जिसे वह ऐसा दस्तावेज या सूचना देने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

(12) कोई भी व्यक्ति, सम्बद्ध प्राधिकरण (अथॉरिटी) की पूर्व लिखित अनुज्ञा के सिवाय प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई व्यापार या कारबार नहीं करेगा या अपने पदीय समनुदेशन के बाहर कोई नियोजन नहीं लेगा।

(13) कोई भी कर्मचारी न तो किसी कारबार में सटटेबाजी करेगा न ही अपने पति या पत्नी या परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसा विनिधान (निवेश) करने की अनुज्ञा देगा जिसमें उसके पदीय कर्तव्यों (ऑफिशियल डियूटीज) के निर्वहन में परेशानी उत्पन्न होने या उस पर असर पड़ने की संभावना हो और व्याज पर किसी व्यक्ति को न तो धन उधार देगा न ही किसी ऐसे व्यक्ति से धन उधार लेगा जिससे उसके पदीय कामकाज (ऑफिशियल डीलिंग्ज) के सम्बन्ध में व्यवहार होने की संभावना है।

(14) कर्मचारी अपने निजी क्रियाकलापों का इस प्रकार प्रबन्ध करेगा ताकि वह आन्यासिक ऋणग्रस्तता या दिवालियापन से बच सके। जब कोई कर्मचारी ऋण के लिए गिरफ्तार होने का दायी पाया जाता है या दिवालियापन का अवलंबन लेता है या जब पाया जाता है कि उसके वेतन का आधा भाग लगातार कुर्क हो रहा है तो वह पदच्युति के लिए दायी होगा। कोई भी कर्मचारी जो, दिवालियापन के लिए विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन हो जाता है तो वह तत्काल पूर्ण तथ्यों को विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों (अथॉरिटीज) को सूचित करेगा। यदि कोई कर्मचारी किन्हीं दापिंडक कार्यवाहियों में अन्तर्विलित हो जाता है तो वह विभागाध्यक्ष, जिससे वह सम्बद्ध है, के माध्यम से इस तथ्य के होते हुए भी कि उसे जमानत पर छोड़ा गया है या नहीं, सक्षम प्राधिकरण (अथॉरिटी) को तत्काल सूचित करेगा वह कर्मचारी जिसे पुलिस अभिरक्षा में, चाहे दापिंडक आरोप के लिए या अन्यथा, अड़तालीस घण्टों से दीर्घतर अवधि के लिए, निरुद्ध किया गया है तो वह विश्वविद्यालय में तब तक अपने कर्तव्य (डियूटी) ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसने संस्था के अध्ययन अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्टडीज) से उस प्रभाव की लिखित अनुज्ञा प्राप्त न कर ली हो।

(15) कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) का प्रत्येक सदस्य विश्वविद्यालय सेवा में प्रथम नियुक्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे अन्तरालों पर, जो सम्बद्ध प्राधिकरण (अथॉरिटी) के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा विहित किए जाएं, ऐसे प्ररूप पर, जिसे विश्वविद्यालय इस निमित्त विहित करे, उसके स्वामित्व के अधीन, उस द्वारा अर्जित या विरासत में आई या उस द्वारा पट्टे या बन्धक पर, उसके स्वयं के नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ली गई समस्त जंगम (चल) या स्थावर (अचल) सम्पत्ति की विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत करेगा।

(16) कोई भी कर्मचारी, सम्बद्ध प्राधिकरण (अथॉरिटी) की पूर्व मंजूरी के सिवाय किसी भी न्यायालय की शरण नहीं लेगा या किसी पदीय कार्य, जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकरण प्रकृति की भर्त्सना का विषय रहा हो, से दोषमोचन हेतु दबाव नहीं डालेगा।

परन्तु इस पैरा की कोई भी बात किसी भी कर्मचारी को उसके निजी चरित्र या उसके द्वारा उसकी निजी हैसियत में किए गए किसी कार्य को दोषमुक्त करने हेतु प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी।

(17) जब कभी कोई कर्मचारी कोई दावा पेश करना चाहता है या उसके प्रति किसी अन्याय के लिए प्रतितोष चाहता है तो वह अपने मामलों को उचित माध्यम द्वारा अग्रेषित करेगा और किसी भी उच्चतर प्राधिकरण (अर्थात् अर्थात्) को अपने अभ्यावेदन की अग्रिम प्रतियां तब तक अग्रेषित नहीं करेगा जब तक कि निम्न प्राधिकरण (लोअर अर्थात्) ने उसका दावा नामंजूर कर दिया हो या अनुतोष देने से इन्कार कर दिया हो या मामले का निपटारा करने में तीन माह से अधिक की देरी हो गई है; परन्तु कोई भी कर्मचारी किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए या किसी अन्य मामले के लिए प्राधिकरणों (अर्थात् अर्थात्) को सम्बोधित संयुक्त अभ्यावेदन में हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं होगा।

(18) कर्मचारी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी आचरण नियम के भंग या अन्यथा के लिए शास्त्रियां अधिरोपित करने और उसके विरुद्ध की गई किसी ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध अपील करने की बाबत विश्वविद्यालय द्वारा तत्पश्चात् बनाए गए परिनियमों के उपबन्धों द्वारा शासित होगा।

33. माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया।—(1) विश्वविद्यालय के कर्मचारी या विश्वविद्यालय के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की दशा में और जो एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए अविनिश्चित रहता है तो उसे किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर निम्नलिखित से गठित माध्यस्थम् अधिकरण को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा:—

- (i) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष;
- (ii) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति; और
- (iii) सम्बद्ध कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति।

(2) विश्वविद्यालय, माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा, अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन में, मंगवाए गए किसी अभिलेख, रिपोर्ट या अन्य सूचना को उसे प्रस्तुत करेगा।

(3) माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उस द्वारा विनिश्चित मामले की बाबत सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा।

(4) परीक्षा के लिए कोई भी छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली (रोल) से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है, और जिसे एक से अधिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा देने के लिए विवर्जित किया गया है ऐसे आदेशों या संकल्प की प्रति की उस द्वारा प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील कर सकेगा और कुलाधिपति, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकेगा और छात्र के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, ऐसे छात्र के अनुरोध पर अध्यादेशों/विनियमों में विनिर्दिष्ट माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या संस्था के किसी अधिकारी या प्राधिकरण (अर्थात् अर्थात्) के विनिश्चय के विरुद्ध, ऐसे समय के भीतर, जो विश्वविद्यालय द्वारा पश्चात्वर्ती बनाए गए परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, कुलाधिपति को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरि प्रबन्ध बोर्ड उस विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकेगा।

(6) समस्त विवाद सिविल न्यायालय, राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की अधिकारिता के अध्यधीन होंगे।

(7) अधिनियम या अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं भी उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई बात या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध न होगी।

34. विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना।—(1) अनुशासन और अनुशासनिक कार्रवाई सम्बन्धी समस्त शक्तियां, कुलपति में निहित होंगी।

(2) कुलपति अपनी समस्त या ऐसी शक्तियों, जिन्हें वह उचित समझे, को ऐसे अन्य व्यक्तियों, जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) परिनियमों के अधीन अनुशासन प्रवर्तित करने की शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित को घोर अनुशासनहीनता का कृत्य समझा जाएगा:—

- (क) विश्वविद्यालय के भीतर किसी संस्था, विभाग के अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य के विरुद्ध, किसी छात्र या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध शारीरिक हमला करना या शारीरिक बल के प्रयोग की धमकी देना;
- (ख) किसी हथियार को ले जाना या प्रयोग करना या प्रयोग करने की धमकी देना;
- (ग) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) के उपबन्धों का कोई उल्लंघन करना;
- (घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित छात्रों की प्राप्तिका, गरिमा और सम्मान का अतिक्रमण करना;
- (ङ) महिलाओं के प्रति कोई अनादरसूचक व्यवहार करना चाहे मौखिक हो या अन्यथा;
- (च) धूस लेने—देने या किसी भी रीति में भ्रष्टाचार का प्रयत्न करना;
- (छ) संस्था और सम्पत्ति का जानबूझ कर विनाश करना;
- (ज) धार्मिक या साम्राज्यिक आधार पर वैमनस्य या असंहिष्णुता पैदा करना;
- (झ) विश्वविद्यालय प्रणाली के शैक्षणिक कृत्यों में किसी भी रूप में अव्यवस्था पैदा करना; और
- (झ) रैगिंग।

(4) कुलपति, अनुशासन को बनाए रखने से और अनुशासन बनाए रखने के हित में ऐसी कार्रवाई करने की, जो उसे उचित प्रतीत हों, अपनी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपनी उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश या निदेश कर सकेगा कि किसी छात्र या छात्रों को—

- (क) निष्कासित किया जाए; या
- (ख) कथित अवधि तक निकाल (निष्कासित) दिया जाए; या
- (ग) कथित अवधि तक विश्वविद्यालय के संकाय/विद्यालय/महाविद्यालय, विभाग या संस्था में अध्ययन के पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाए; या
- (घ) ऐसी राशि का जुर्माना किया जाए, जो विनिर्दिष्ट किया जाए; या

(ङ) विश्वविद्यालय या संकाय/विद्यालय/महाविद्यालय की या विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं देने से एक या एक से अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए; या

(च) सम्बन्धित छात्र या छात्रों की उस परीक्षा या परीक्षाओं, जिनमें वह/वे बैठे हैं, के परिणाम रद्द किए जाएं।

(5) संकाय/विद्यालय/महाविद्यालयों के अधिष्ठाता (डीन), हॉलों के अध्यक्ष (हैड), संकाय अधिष्ठाता (डीन ऑफ फैकल्टीज), विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों के अध्यक्षों (हैडज), दूरवर्ती शिक्षा का अध्यक्ष (हैड), और पुस्तकाल्याध्यक्ष को छात्रों पर विश्वविद्यालय में, उनके अपने—अपने संकाय/विद्यालय/महाविद्यालयों, संस्थाओं संकायों और अध्यापन विभागों में अनुशासनिक प्राधिकार का प्रयोग करना होगा जो संस्थाओं, आवास हॉलों और सम्बन्धित विभागों में अध्यापन के उचित संचालन के लिए कुलपति के अनुमोदन के अधीन, आवश्यक हो।

(6) कुलपति और यथापूर्वोक्त अधिकारियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचार के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विस्तृत विनियम बनाए जाएंगे।

(7) प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र से ऐसी घोषणा पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह प्रवेश पाने पर, स्वयं को कुलपति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों (अथारिटीज), जिन्हें अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों, जो विश्वविद्यालय द्वारा तद्धीन बनाए गए हैं, के अधीन अनुशासन प्रयोग करने का प्राधिकार निहित किया जा सके, की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन करता है।

35. रैगिंग का प्रतिषेध और रैगिंग के लिए दण्ड।—(1) विश्वविद्यालय या संकाय/विद्यालय/महाविद्यालय या संस्था के परिसर के भीतर या संकाय/विद्यालय/महाविद्यालय के बाहर किसी भी प्रकार की रैगिंग का सर्वथा प्रतिषेध होगा।

(2) रैगिंग का कोई वैयक्तिक या सामूहिक कार्य या व्यवहार घोर अनुशासनहीनता समझी जाएगी और इसके लिए इस परिनियम के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

(3) इस परिनियम के प्रयोजनों के लिए रैगिंग से साधारणतया ऐसा कोई कार्य, आचरण या व्यवहार अभिप्रेत है जिसके द्वारा वरिष्ठ छात्रों की प्रभुतापूर्ण शक्तियों या प्रासिथति (हैसियत) को नए भर्ती किए छात्रों या उन छात्रों, जिन्हें किसी भी रूप में अन्य छात्रों से कनिष्ठ या अश्रेष्ठ समझा गया है, पर उपस्थापित किया जाए और इसके अन्तर्गत ऐसे वैयक्तिक या सामूहिक कार्य या व्यवहार है—

- (क) जिनमें शारीरिक हमला या शारीरिक बल प्रयोग करने की धमकी अन्तर्वलित हो;
- (ख) जो छात्रों (महिला छात्रों) की प्रासिथति, गरिमा और सम्मान का अतिक्रमण करते हों;
- (ग) जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित छात्रों की प्रासिथति, गरिमा और सम्मान का अतिक्रमण करते हों;
- (घ) जिनसे छात्रों का उपहास और तिरस्कार हो तथा उनका स्वाभिमान प्रभावित होता हो;
- (ङ) जिनमें गाली और छेड़छाड़, अशिष्ट इशारों तथा अश्लील व्यवहार का समावेश हो।

(4) संकाय/विद्यालय/महाविद्यालय का अधिष्ठाता, विभाग या संस्था का अध्यक्ष, संकाय/विद्यालय/महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के छात्रावास या निवासों के हॉलों के प्राधिकारी (अथॉरिटी) रैगिंग की घटना की किसी भी सूचना पर तुरन्त कार्रवाई करेंगे।

(5) खण्ड (4) में किसी बात के होते हुए भी, अधिकारी रैगिंग की किसी भी घटना की जांच भी कर सकेगा और उनकी पहचान, जो रैगिंग में शामिल हैं की रिपोर्ट तथा घटना के स्वरूप की रिपोर्ट कुलपति को कर सकेगा।

(6) अधिकारी रैगिंग का अपराध करने वालों की पहचान तथा रैगिंग की घटना के स्वरूप को स्थापित करते हुए एक प्रारम्भिक रिपोर्ट भी कुलपति को प्रस्तुत कर सकेगा।

(7) यदि संकाय/विद्यालय/महाविद्यालय के अधिष्ठाता या विभाग या संस्था के अध्यक्ष (हैड) का समाधान हो जाता है कि लिखित में अभिलिखित किसी भी कारण से ऐसी जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहारिक नहीं है, तो वह कुलपति को तदनुसार परामर्श दे सकेगा।

(8) जब कुलपति का समाधान हो जाता है कि ऐसी जांच करना समीचीन नहीं है तो उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(9) खण्ड (3) (क), (ख) और (ग) में वर्णित रैगिंग की घटनाओं के होने को प्रकट करने वाली खण्ड (5) या (6) के अधीन रिपोर्ट या सुसंगत प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा खण्ड (7) के अधीन अवधारण की प्राप्ति पर कुलपति छात्र या छात्रों को विनिर्दिष्ट वर्षों के लिए निष्कासित करने के निदेश या आदेश करेगा।

(10) कुलपति रैगिंग के अन्य मामले में आदेश या निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या छात्रों को निष्कासित कर दिया जाए या कथित अवधि तक किसी संकाय/विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रम, विभागीय परीक्षा में प्रवेश के लिए एक या अधिक वर्षों के लिए उसे/उन्हें प्रवेश न दिया जाए या सम्बन्धित छात्र या छात्रों के उस परीक्षा या परीक्षाओं, जिनमें वह/वे बैठा है/बैठे हैं, के परिणाम को रद्द कर दिया जाए।

(11) यदि किसी छात्र को, जिसने विश्वविद्यालय की उपाधियां प्राप्त की हैं, इस परिनियम के अधिनियम के अधीन दोषी पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधियों को वापस लेने के लिए समुचित कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

(12) इस परिनियम के प्रयोजन के लिए रैगिंग का दुष्प्रेरण, चाहे रैगिंग के किसी कार्य, व्यवहार या उद्दीपन के रूप में हो, को भी रैगिंग समझा जाएगा।

(13) विश्वविद्यालय प्रणाली के अन्तर्गत समस्त संस्थाएं परिनियम के अधीन जारी अनुदेशों/निदेशों को कार्यान्वयित करने के लिए बाध्यकारी होंगी और परिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की अभिप्राप्ति के लिए कुलपति को सहायता और परामर्श देगी।

36. मानद उपाधियों तथा विद्या सम्बन्धी उपाधियों का प्रदान किया जाना।—(1) विद्या परिषद् को, कुलपति की सिफारिशों पर और कुलाधिपति द्वारा पुष्टि किए जाने के अध्यधीन मानद उपाधियां और विद्या सम्बन्धी उपाधियां, व्यक्तियों को उद्योग में उनकी ख्याति तथा प्राप्तियों या सामाजिक/सामुदायिक सेवा/विज्ञान, कला विषयों (हायूमनटीज), इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन, शिक्षा, फार्मसी, आतिथ्य, मीडिया, फैशन, स्थापत्यकला, फाइन आर्ट में विद्या (लर्निंग) में उनके योगदानों के फलस्वरूप या जिन्होंने औद्योगिक/वैज्ञानिक संसार में अपनी स्थिति (पद) स्थापित की है और जिन्हें ऐसी मानद उपाधियों के प्राप्त करने के लिए सही और उचित पाया गया है, प्रदान करने की शक्ति होगी।

(2) विद्या परिषद् की मानद उपाधियों तथा विद्या सम्बन्धी उपाधियां (डिस्टिंक्शनज) प्रदान करने सम्बन्धी समस्त सिफारिशें, कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन, कुलपति तथा प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त अन्य दो सदस्यों से गठित समिति के माध्यम से की जाएंगी।

(3) मानद उपाधियां या विद्या सम्बन्धी उपाधियां (डिस्टिंक्शनज) दीक्षांत समारोह में प्रदान की जाएंगी और उन्हें या तो व्यक्तिगत रूप से या अनुपस्थिति में लिया जा सकेगा।

(4) उन व्यक्तियों, जिन्हें मानद उपाधियां प्रदान की जानी हैं, के दीक्षांत समारोह में प्रस्तुति (उपस्थापन) कुलपति द्वारा या प्रयोजन के लिए कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(5) प्रबन्ध बोर्ड के पास ऐसे दीक्षांत समारोह में अपनाए जाने वाले प्रक्रिया नियमों को बनाने या उनमें परिवर्तन करने का प्राधिकार होगा।

(6) विद्या परिषद्, उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त किसी भी विद्या सम्बन्धी उपाधि या प्रदान किए गए किसी प्रमाण पत्र या डिप्लोमे को उचित और पर्याप्त कारण से वापिस ले सकेंगे:

परन्तु ऐसा संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, जो उस नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए या हेतुक दर्शित करने का लिखित नोटिस न दे दिया जाए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित किया जाए और जब तक विद्या परिषद् द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हो, और किसी साक्ष्य पर, जो वह उसके समर्थन में पेश करे, विचार न कर लिया जाए।

37. अध्येतावृत्तियां छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक, पारितोषिक आदि संस्थित करना।—(1) विद्या परिषद् प्रत्येक संस्था के समुचित संकाय के परामर्श से कार्रवाई प्रारम्भ करेगी तथा ट्यूशन फ्रीशिप अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक, पारितोषिक आदि संस्थित किए जाने की सिफारिश करेगी। विद्या परिषद् इन पुरस्कारों (अवार्डज) की संस्तुति कुलाधिपति को पुष्टि हेतु करेगी।

(2) संस्था के संकाय अधिष्ठाता (डीन ऑफ फैकलटी) का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित ऐसी स्कीमों के लिए अपनी संस्था के बजट में पर्याप्त उपबन्ध सुनिश्चित करे।

(3) प्रबन्ध बोर्ड को ट्यूशन फ्रीशिप, अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों, पारितोषकों या अन्य को, जो उस द्वारा अनुमोदित किए जाएं, प्रदान करने, निलम्बित करने या रद्द करने के प्रयोजन के लिए नियम या विनियम बनाने की पूर्ण शक्तियां होंगी:

परन्तु ट्यूशन फ्रीशिप, अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों, पारितोषकों, मैरिट-कम मीनज छात्रवृत्तियों, शिक्षा ऋणों और अन्य रियायतों की विद्यमान स्कीमें प्रत्येक घटक संस्था की बाबत उस समय तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि उन्हें कुलाधिपति द्वारा प्रतिस्थापित, परिवर्तित अन्यथा निपटा नहीं दिया जाता।

(4) शिक्षा शुल्क फीस (ट्यूशन फीस), रियायतें, मैरिट जो विद्या परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाए के आधार पर प्रदान की जाएगी।

38. प्रवेश पॉलिसी।—(1) अधिनियम तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अध्यधीन स्नातक पूर्व/एकीकृत/स्नातकोत्तर/डॉक्टरल प्रोग्रामों में प्रवेश सर्वथा राज्य स्तर/अखिल भारतीय स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में मैरिट/रैंक तथा अर्हता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों/ग्रेडों तथा पाठ्यक्रमेतर क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर दिया जाएगा। यदि किसी प्रोग्राम के लिए राज्य स्तर/अखिल भारतीय स्तर पर कोई प्रवेश परीक्षा संचालित नहीं की गई है तो विश्वविद्यालय अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षा संचालित कर सकेगा।

यदि विश्वविद्यालय द्वारा कोई परीक्षा संचालित नहीं की जाती है, अर्हता परीक्षा में मैरिट प्रवेश का मानदण्ड होगी।

विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रोग्रामों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदण्ड और प्रक्रिया समय-समय पर अध्यादेशों/विनियमों के माध्यम से विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(2) समस्त पाठ्यक्रमों में पच्चीस प्रतिशत स्थान (सीटें) हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी (बोनाफाइड हिमाचली) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से विकलांग तथा अन्य सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए स्थान (सीटें) उस विस्तार तक आरक्षित रखेगा जो हिमाचल प्रदेश सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे:

परन्तु यदि आरक्षित प्रवर्गों के अधीन आबंटित स्थान (सीटें) रिक्त रह जाते हैं तो स्थान (सीटें) सामान्य प्रवर्ग में सम्परिवर्तित कर दिए जाएंगे तथा सामान्य प्रवर्ग से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को प्रस्थापित (ऑफर) किए जाएंगे।

39. छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस की बाबत उपबन्ध—अधिनियम की धारा 32 के अधीन किए गए उपबन्धों के अतिरिक्त, फीस संरचना का विनिश्चय करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:—

- (1) विश्वविद्यालय विभिन्न शैक्षणिक प्रोग्रामों के लिए स्नातक पूर्व, स्नातकोत्तर, अनुसंधान तथा पोस्ट डॉक्टरल छात्रों से ऐसी फीस प्रभारित करेगा जो कुलाधिपति के अनुमोदन से वित्त समिति द्वारा अवधारित की जाए।
- (2) विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की सिफारिशों के अनुसार तथा कुलाधिपति के अनुमोदन से छात्रों और अनुसंधान विद्वानों (स्कॉलरज) को फीस अधित्यजन (फीस वेवरज) भी प्रदान करेगा।
- (3) फीस को जमा करने, विलम्ब जुर्माने, संस्था के शैक्षणिक प्रोग्रामों की नामावली (रोल) से नामों की प्रविष्टि/हटाया जाना और ऐसे अन्य विषयों जो विद्या परिषद् द्वारा विनिश्चित किए जाएं, की बाबत प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकथित की जाएगी।
- (4) विश्वविद्यालय फीस निम्नलिखित मुख्य प्रवर्गों के अधीन प्रभारित की जाएगी:—
 - (क) प्रवेश फीस।
 - (ख) शिक्षा शुल्क फीस (ट्यूशन फीस)।
 - (ग) चिकित्सा फीस।
 - (घ) परीक्षा फीस।
 - (ङ) छात्र सेवा निधि।
 - (च) विश्वविद्यालय रजिस्ट्रीकरण फीस।
 - (छ) संस्थागत विकास निधि।
 - (ज) अवधान द्रव्य (कॉशन मनी) (प्रतिदेय केवल प्रवेश के समय एक बार)।
 - (झ) ऐसे शैक्षणिक, सामाजिक तथा आमोद-प्रमोद सम्बन्धी निधियों, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, के लिए अभिदाय।
 - (झ) परिवहन फीस (यथा अपेक्षित)।
 - (ट) छात्रावास फीस (यथा अपेक्षित)।
 - (ठ) ऐसी अन्य फीस जो समय-समय पर विहित की जाए।
- (5) विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के अनुरोध पर ऐसी फीस, जैसी प्रबन्ध बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित की जाए, सहित विनिर्दिष्ट प्रपत्र पर निम्नलिखित दस्तावेज जारी किए जाएंगे:—

(क) ड्यूपलीकेट प्रमाण पत्र/उपाधि ।

(ख) अनन्तिम प्रमाण पत्र/उपाधि ।

(ग) योग्यता (मैरिट) प्रमाण पत्र ।

(घ) डिटेल्ड मार्क्स कार्ड (डी०एम०सी०) ।

(ङ) ड्यूपलिकेट ३००८०सी० ।

(च) प्रवेश फार्म ।

(छ) अनुलिपि ।

(ज) पुनः परीक्षा (रीअपीयर) फार्म ।

(झ) पुनर्मूल्यांकन फार्म ।

(ञ) परीक्षा फार्म ।

(ट) रजिस्ट्रेशन फार्म ।

(ठ) माइग्रेशन प्रमाण पत्र ।

(ड) गोपनीय परिणाम ।

(ढ) छात्र द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज ।

(6) प्रबन्ध बोर्ड को समय-समय पर विभिन्न फीसों जुर्मानों और अन्य नियत प्रभारों को पुनरीक्षित करने तथा अतिरिक्त फीसों, जुर्मानों और अन्य प्रभारों, जो समय-समय पर अवधारित किए जाएं, को भी विनिर्दिष्ट करने की शक्ति होगी।

40. विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों (सीटों) की संख्या की बाबत उपबन्ध—(1) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए स्थानों (सीटों) की कुल संख्या विद्या परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाएगी तथा कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित की जाएंगी। तथापि प्रत्येक पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रवर्गों के लिए स्थानों (सीटों) के लिए आरक्षण सरकार के नियमों के अनुसार रखा जाएगा और विभिन्न प्रवर्गों के लिए रिक्तियां खुले प्रवर्ग के अध्यर्थियों द्वारा भरी जा सकेंगी।

(2) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों (सीटों) की संख्या कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन विद्या परिषद् के विवेक पर बढ़ाई या घटाई जा सकेंगी।

(3) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों (सीटों) का वितरण विद्या परिषद् द्वारा कुलाधिपति के अनुमोदन से विनिश्चित किया जाएगा।

41. शैक्षणिक कार्यकलाप अधिष्ठाता (डीन ऑफ अकेडमिक अफेयरज)—शैक्षणिक कार्यकलाप अधिष्ठाता (डीन ऑफ अकेडमिक अफेयरज) कुलपति को सीधे रिपोर्ट करेगा तथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा:—

(1) विश्वविद्यालयों के विभिन्न संकायों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा स्थापित किए जाने वाले नए शैक्षणिक प्रोग्रामों के लिए पाठ्य विवरण विकसित करना।

(2) विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्रोग्रामों के विद्यमान शैक्षणिक प्रोग्रामों के पाठ्य विवरण को अद्यतन करना।

(3) अन्तर विषयक तथा संयुक्त उपाधि शैक्षणिक प्रोग्राम और उनके पाठ्य विवरण विकसित करना।

(4) समुचित प्रत्यायन/व्यावसायिक अभिकरणों, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों, से प्रत्यायन प्राप्त करना।

(5) भारत तथा विदेश, दोनों की ख्याति प्राप्त संस्थाओं शैक्षणिक सहयोग विकसित करना।

(6) नए शैक्षणिक प्रोग्रामों की स्थापना तथा कठिपय अन्य प्रोग्रामों को निरस्त करने के बारे में कुलपति को सिफारिश करना।

(7) कैम्पस छात्रों के लिए राज्य/केन्द्रीय सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति स्कीमों को नियन्त्रित तथा क्रियान्वित करना।

(8) मुख्य सम्पादक तथा समन्वय की हैसियत से इन-हाउस मैगजीनों और अन्य इसी प्रकार के प्रकाशनों को प्रकाशित कराना।

42. संकाय अधिष्ठाता (डीन ऑफ फैकल्टी)।—संकाय अधिष्ठाता (डीन ऑफ फैकल्टी) कुलपति को सीधे रिपोर्ट करेगा तथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा:—

(1) संकाय के अधीन शैक्षणिक इकाईयों (विद्यालय, विभाग, संस्थाएं) के कामकाज तथा विकास का निरीक्षण करना और ऐसे कर्तव्यों के पालन में शैक्षणिक कार्यकलाप अधिष्ठाता (डीन ऑफ अकैडमिक्स) के साथ समन्वय करेगा।

(2) कुलपति को उसके अधीन संकाय के समस्त शैक्षणिक तथा प्रशासनिक मामलों के सम्बन्ध में परामर्श (राय) देगा।

(3) विभिन्न शैक्षणिक इकाईयों अर्थात् संकाय के विभागों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्रमुख (हैडज) उसे नियमित आधार पर रिपोर्ट करेंगे।

43. सहकारी अध्ययन तथा नियोजन अधिष्ठाता (डीन ऑफ कोआपरेटिव स्टडीज एण्ड प्लेसमैट)।—सहकारी अध्ययन तथा नियोजन अधिष्ठाता (डीन ऑफ कोआपरेटिव स्टडीज एण्ड प्लेसमैट) कुलपति को रिपोर्ट करेगा तथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा:—

(1) उच्च अध्ययन की संस्थाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों चिन्हित करना जहां पर छात्रों को भावी नियोजकों के साथ, सहकारी शैक्षणिक शिक्षा (कोऑपरेटिव अकेडमिक ऐजुकेशन) तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण व्यवस्थाओं के अधीन नियोजित किया जा सके।

(2) इस व्यवस्था के अधीन चयनित संख्या में छात्र शैक्षणिक वर्ष के लिए एक भाग में ईटरनल विश्वविद्यालय में अध्ययन करेंगे और शैक्षणिक वर्ष का एक भाग प्रशिक्षण स्थल पर बिताएंगे। शैक्षणिक प्रशिक्षण तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण की इस सहकारी व्यवस्था की समाप्ति पर नियोजन अवसरों की ओर अग्रसर हो सकेंगे।

44. दूरवर्ती शिक्षा (विद्या) अधिष्ठाता (डीन ऑफ डिस्टॅन्स लर्निंग)।—दूरवर्ती शिक्षा (विद्या) अधिष्ठाता (डीन ऑफ डिस्टॅन्स लर्निंग) कुलपति को रिपोर्ट करेगा और विश्वविद्यालय के अधीन समस्त शैक्षणिक प्रोग्रामों का प्रभारी होगा। इसके कर्तव्य पश्चात्वर्ती परिनियम में यथाविनिर्दिष्ट रूप से नियत किए जाएंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव।

[Authoritative English Text of this Department Notification number EDN-A-Ka(1)-21/07-
Loose dated, 17th June, 2009 as required in clause (3) of article 348 of the constitution of India].

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 17th June, 2009

No. EDN-A-Ka (1)-21/07.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No. 3 of 2009), the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following First Statutes of the Eternal University, Baru Sahib, Himachal Pradesh, namely :—

THE FIRST STATUTE OF THE ETERNAL UNIVERSITY, HIMACHAL PRADESH, BARU SAHIB, DISTT. SIRMOUR

1. Short title and commencement.—(1) These Statutes may be called the First Statutes of the Eternal University, Himachal Pradesh, Baru Sahib, 2009.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these Statutes unless there is any thing repugnant to the subject or context:—

(i) “Act” means the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008.

(ii) “Authority” means any of the Authority of the University;

(iii) “employee” means all the employees whether teaching or non-teaching of the University;

(iv) “Officer or Officers” means Officers of the University; and

(v) “section” means a section of the Act;

(2) All words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Other Officers of the University:—In addition to the officers specified in section 11, there shall be the following other persons declared officers of the University, namely:—

(i) the Dean of Academics Affairs;

(ii) the Dean of Faculty (s);

(iii) the Dean of Studies;

(iv) the Dean of Students Welfare;

(v) the Dean of Postgraduate Studies;

(vi) the Dean of Co-operative Studies & Placement;

(vii) the Dean of Distance Learning/Education;

(viii) the Controller of Examination;

(ix) the Librarian.

4. Terms and conditions of service of the Chancellor and his powers and functions.—(1) In addition to the powers conferred upon him, under sub-section (4) of section 12 the Chancellor shall exercise the following powers, namely:—

(a) The Chancellor shall be the chairperson of the Governing Body.

(b) The Chancellor shall have the right to cause an inspection to be made, by such person or persons as he may direct, of the University, or any institution maintained by the University, or of its Faculty/school/college, including the buildings, laboratories, record and equipment thereof and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by it, or to cause an inquiry to be made in a like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University, or the institution maintained by it;

(c) In case of inspection or inquiry relating to any of the affairs of the University or a Faculty/school/college maintained by it, the Chancellor may communicate to the Vice-Chancellor the result of such inspection or inquiry together with his views thereon and advise with regard to the action to be taken thereon as the Chancellor may pleased to offer and on receipt of the report made by the Chancellor, the Vice-Chancellor shall communicate forth with to the board of Management, the result of the inspection or inquiry and the views of the Chancellor and the advice rendered by him upon the action to be taken thereon and the board of Management shall communicate through the Vice-chancellor to the Chancellor such action, if any as it proposes to take or has been taken by it upon the results of such inspection or inquiry.

(d) Where the Board of Management or the Management of the Faculty/school/college, as the case may be, does not take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may after considering any explanation furnished or representation made by the Board of Management, as the case may be, issue such direction as he may deem fit and the University or the Faculty/school/college shall comply with such directions.

(e) Without prejudice to the foregoing provisions, the Chancellor may, by order in writing, annul proceedings of the University or of its any authority or the decision of any officer of the University, which is not in conformity with the provisions of the Act or the subsequent Statutes made by the University:

Provided that before making such order, the Chancellor shall call upon the University, or its academic unit as the case may be, its authority or the officer, to show cause why such an order should not be made and if any cause is shown within the period specified by him in this behalf, shall consider the same.

(2) When the Chancellor is away from the Head-quarter or if he is unable to perform his duties due to ill health or for any other reasons the Vice-Chancellor, and if the Office of the Vice-Chancellor is also vacant such person, as the Chancellor may appoint, shall perform the duties of

the Chancellor, and the Vice-Chancellor or as the case may be the person appointed by the Chancellor shall, at the earliest opportunity, report the action taken by him for confirmation to the Chancellor:

Provided that if the action taken is not approved, the decision thereon of the Chancellor shall be final.

5. Terms and conditions of service and powers and functions of the Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University.

(2) The Vice-chancellor shall be entitled to rent free residence and full maintenance thereof.

(3) The Vice-chancellor may resign from his office by serving a notice of one month in writing under his hand addressed to the Chancellor:

Provided that where the circumstances so warrant, the Chancellor may waive off the period of notice and accept the resignation forthwith.

(4) If the office of the Vice-Chancellor becomes vacant due to, resignation or otherwise, the Chancellor may appoint any person of his choice who shall perform the duties of the Vice-Chancellor, until the vacancy is filled up on regular basis or until the Vice-Chancellor resumes his duties, as the case may be and the person so appointed shall have all the powers of the Vice-Chancellor and shall be entitled to the privileges of the Vice-Chancellor:

Provided that such interim arrangement shall not exceed a period of one year from the date on which such an arrangement is made.

(1) In addition to the power conferred upon him under section 13 of the Act the Vice-Chancellor shall exercise and perform the following powers and functions, namely:—

(2) The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at, and to address any meeting of any authority or anybody of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall exercise control over the affairs of the University and shall give effect to the decisions of all the authorities of the University in letter and spirit and shall ensure that they are not contradictory in nature and practice.

(4) The Vice-Chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the University and he may delegate any such powers to such person or persons as he may deem fit.

(5) The Vice Chancellor shall make appointments of the Deans, Principals, Professors, Associate Professors, Readers, Lecturers, Librarian other teachers and such academic staff of Faculty/school/colleges and Institutions established by the University, as may be necessary, on the recommendations of the selection committees constituted for the purpose by the Chancellor. The Vice-chancellor shall be the chair person of such committee.

Provided that the Vice-Chancellor may make short-term appointments, for a period not exceeding one year, of such persons as may be considered necessary for the functioning of the University.

(6) The Vice-Chancellor shall grant leave of absence to any officer of the University and make necessary arrangements for the discharge of the functions of such an officer during the period of his absence.

(7) The Vice-Chancellor shall grant leave of absence to any employee of the University in the specified manner and if he so decides may delegate such powers to any other officer or officers of the University.

(8) The Vice-chancellor shall have the authority to take disciplinary action against any employee of the university as specified by the subsequent statute:

Provided that if the decision taken by the authority or body on the report of the Vice-Chancellor affects adversely any person in the service of the University, the person may appeal to the Chancellor within thirty days from the date on which decision was communicated to him and the decision of the Chancellor on such appeal shall be final.

(9) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the various authorities/bodies of the University, except the Governing body.

(10) If in the opinion of the Vice-Chancellor it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under the Act, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(11) The Vice-chancellor shall as a vital link with the UGC, AICTE, NCTE, Council for Architecture/Universities/Pharmacy Council, NAAC/NBA, other National and International agencies and other regulatory bodies. To have liaison with Directorates of Higher Education, Himachal Pradesh for providing healthy and cordial relations with the Government Departments with which the University has to deal with.

(12) The Vice-chancellor shall take steps and bring about NAAC/NBA accreditation for Institutions/Departments, to provide guidance and logistic support for getting the highest possible grade for the Institutions. To help the Departments and Institutions get maximum amounts of financial grants from various funding agencies including UGC, AICTE, State and Central Governments.

(13) To keep abreast with the latest Educational policies of both the State Government as well as Central Government and also to apprise the Department/Institutions about the same, guiding them in their proper implementation.

(14) The Vice-Chancellor shall, at the close of each academic year, in the manner specified in the subsequent Statutes or Ordinances, assess and evaluate the teaching and research work done by the members of the Faculty, if necessary through a committee of experts appointed by him. On such assessment or the evaluation, if the Vice-Chancellor is of the opinion that the work and conduct of any member of the Faculty is not satisfactory, he may, in the manner as laid down in the subsequent Statutes or Ordinances, initiate or cause to be initiated action against such a member.

(15) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be specified by subsequent Statutes made by the university under the Act.

(16) The Vice-Chancellor shall see that the provisions of the Act, statutes, ordinances and the regulations are duly observed and he shall take all necessary steps to ensure such observance.

6. Appointment, terms and conditions of service of the Registrar and his powers and functions.—(1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of a Selection Committee constituted for the purpose on the terms and conditions of service as specified by the Subsequent Statutes.

(2) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is by reason of illness or absence for any other cause unable to perform the duties of the office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint subject to the approval of the Chancellor.

(3) The Registrar shall be a whole time salaried officer of the University and work under the control of the Vice-Chancellor.

(4) The Registrar shall be the *ex-officio* Member Secretary of the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council, but shall not have the right to vote.

(5) It shall be the duty of the Registrar,—

- (a) to receive applications for admission into the University;
- (b) to keep a permanent record of all syllabi, curricula and information connected therewith;
- (c) to assist the Controller of Examination for the conduct of examinations as may be provided by the Subsequent statutes.
- (d) to maintain a register of all degrees, diplomas and academic distinctions conferred by the University;
- (e) to have the custody of the record, the common seal and other properties of the University as the Chancellor shall commit to his charge;
- (f) to supply to the Chancellor copies of the agenda of meetings of the authorities of the University as soon as they are issued and the minutes of the meetings of the authorities ordinarily within a month of the holding of the meetings;
- (g) to represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign power of attorney, verify pleadings and depute his representative for the purpose;
- (h) to enter into agreements/contracts, sign documents and authenticate records on behalf of the University; and
- (i) to perform such other functions as may from time to time be assigned to him by the Vice-chancellor and the Chancellor.

7. Appointment, terms and conditions of service of the Chief Finance and Accounts Officer and his powers and functions.—(1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Selection Committee constituted for the

purpose and chaired by the Vicechancellor on terms and conditions of the service as specified by the Subsequent Statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall be a whole time salaried officer of the University and shall work under the control of the Vice-Chancellor.

(3) When the office of the Chief Finance and Accounts Officer is vacant or when the Chief Finance and Accounts Officer is by reason of illness or absence for any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose. This appointment may be good for one year or till his permanent replacement is appointed by the Chancellor.

(4) The Chief Finance and Accounts Officer shall,—

- (a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise it as regard its financial policy;
- (b) be responsible for the proper maintenance of the accounts of the University; and
- (c) perform such other financial functions as may be assigned to him by the Vice-chancellor as may be specified in the Subsequent Statutes or the Ordinances of the University.

(5) Subject to the control of the Vice-Chancellor, the Chief Finance and Accounts Officer shall,—

- (a) hold and manage the property and investments including trust and endowed property for furthering any of the objects of the University;
- (b) ensure that the limits fixed by the Finance Committee for recurring and non-recurring expenditure for the financial year are not exceeded and that all moneys are expended on the purposes for which they are granted or allotted;
- (c) be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the University for the next financial year and for presentation of the same to the Board of Management, through the Vice-Chancellor and also for ensuring that the financial sanctions are obtained in time;
- (d) keep a constant vigilance on the state of the cash and bank balances and on the state of investments;
- (e) watch and progress the collection of revenue and advise on the methods of collection employed;
- (f) keep all money belonging to the University in a Scheduled Bank approved by the Chancellor;
- (g) ensure that the registers of the properties, buildings, land, furniture and equipment of the University are maintained up-to-date and that the stock checking of equipment and other consumable material in all offices, teaching departments, faculty/school/colleges and institutions maintained by the University is conducted at regular intervals, or as may be required from time to time;

(h) call for from any office or department or faculty/school/college or institution under the University any information or returns that he may consider necessary to discharge his financial responsibilities; and

(i) to prepare and issue agenda and maintain minutes of the meetings of the Finance Committee, and conduct the correspondence on behalf of the Finance Committee.

(6) The receipt of the Chief Finance and Accounts Officer or of the person or persons duly authorized in this behalf by the Chancellor for any money payable to the University shall be sufficient discharge for the same.

8. Appointment, terms and conditions of service of the Dean of Studies and his powers and functions.—(1) There shall be appointed a Dean of faculty in each faculty/School of Studies by the Chancellor, on the recommendations of the selection committee chaired by the Vice-chancellor.

(2) Subject to the approval of the Chancellor, every Dean shall be appointed from amongst the persons, who are or who have been the teachers of any University, not below the rank of Reader (Associate Professor), or equivalent experience in research and industry by the Vice-Chancellor on the recommendations of the Selection Committee constituted for the purpose and chaired by him.

(3) When the office of the Dean of studies is vacant or where the Dean is by his, absence or any other cause unable to perform the duties of his office, the duties of his office shall be performed by any person designated by the Vice-chancellor and confirmed by the Chancellor.

(4) The Dean of faculty shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of teaching and research in the Faculty/School of Studies.

(5) The terms and conditions of service and duties and the powers of the Dean of studies shall be as may be provided for by the Subsequent Statutes and ordinances.

9. Appointment, terms and conditions of service of the Controller of Examinations and his powers and functions.—(1) The Controller of Examinations shall be a whole time salaried officer of the university and appointed by the Chancellor, on the recommendations of the selection committee chaired by the Vice-Chancellor.

(2) The terms and conditions of service of the Controller of Examinations shall be as of the Registrar and such other officers of the University.

(3) The Controller of Examinations shall exercise and perform the following powers and functions, with the approval of the Vice-Chancellor. He/she shall work under the direct control of the Vice-Chancellor:—

(i) to arrange for and supervise the work of examinations of the University in accordance with the manner specified by Regulations and Rules of the University;

(ii) to perform such other duties as may be specified in the Subsequent Statutes, the Ordinances the Regulations and Rules or as may be required from time to time, the Vice-Chancellor or the Chancellor;

(iii) to conduct all University examinations and make preparatory arrangements, there for Examinations, Setting up of the examination centers, appointment of Supervisory and

invigilation and other staff, ensuring smooth, efficient, fair and transparent conduct of examinations, the printing and supply of Answer Books and receipt back of the used' Answer Books' from the Centers;

- (iv) to set the question papers for all University examinations by the examiners/paper setters, ensuring that the Question Papers set are in accordance with the approved scheme of examinations and as per the prescribed syllabi for a particular course/paper. The confidentiality of the entire process of paper setting at all stages must be maintained in total;
- (v) to get the question papers printed from some reputed but confidential Presses. The name and address and phone numbers etc. of the Press must be kept as secret. The printed Question Papers must be received back from Press well before the start of the examination so that these reach the examination centers well in time. The entire transportation process must also be kept confidential to prevent any kind of leakage of Question Papers;
- (vi) to fix the commencement dates of various examinations, to prepare the date sheet and schedule for all examinations to be held during the next one year and publishing the same well in time for the information of all concerned;
- (vii) to get the Answer books for all University Examinations evaluated so that the award lists in all such cases are supplied to examination branches/computer section for tabulation, scrutiny and declaration of various examinations results. To ensure that all examination results are declared and published within the schedule fixed for the purpose and the public widely informed accordingly. Rectification of results, rechecking and re-evaluation of Answer Books, wherever permissible;
- (viii) to get the Detailed Marks Cards(DMCs), Degrees and other relevant testimonials prepared for all those students passing out from the University and the same be supplied to students /faculty/school/colleges / Institutions, within the period specified for the purpose;
- (ix) to make arrangements for verifications of credentials of students, who had passed out of the University and make application either for Jobs or admissions in India or abroad and would like their credentials to be verified by the University;
- (x) to prepare and maintain accounts for secrecy funds, get the same checked/counter signed from the specified authority and keep permanent records for all such confidential transactions/accounts;
- (xi) to take steps for continuous examinations reforms so as to keep updating the existing Statutes, Regulations and Rules relating to examinations, to propose new rules and regulations in relation to examinations and getting the same approved from the concerned bodies of the University;
- (xii) to draw out the lists of examiners, paper setters, evaluators, centre superintendents, centre Inspectors, members of flying squads, observers, Chief coordinators, Coordinators of various Examinations, both traditional and Entrance tests Examinations and get the same approved with appropriate revisions, if any, by the competent bodies of the University;

- (xiii) to sign Detailed Marks Cards, Degrees and all other certificates and testimonials, wherever it is required to do so. The confidential seals, stamps including the ones carrying signatures be got prepared and kept in safe custody for use at the required time. It will be the responsibility of the Controller of Examination to ensure that these confidential seals are not misused or tampered or lost by anyone for any ulterior purpose. Issuance of duplicate DMCs' and Degrees shall be issued on an application by the candidate on payment of requisite fee;
- (xiv) to keep liaison with Dean Faculty of Institution/Heads of Departments with regard to student's enrolments, conduct of examinations and on other issues relating to students and teachers;
- (xv) to work under the direct superintendence and direction of the Vice- Chancellor
- (xvi) to receive the Examination forms and issuance of admit card for university examinations;
- (xvii) to countersign and sanctioning of various TA/DA bills in respect of staff, examiners, supervisory, invigilation and other staff appointed for the conduct of examinations, Evaluation/Re-evaluation of Answer Books and tabulation/declaration/publication of Examination results; and
- (xviii) to perform any other duty or function allotted to him by the Vice-Chancellor and the Chancellor.

4. The Vice-Chancellor may authorise any other person to exercise any or all of the powers of Controller of Examinations in his absence.

10. Appointment, terms and conditions of service of the Dean of Student Welfare (DSW) and his powers and functions.—(1) The Dean of Student Welfare (DSW) shall be appointed by the Vice Chancellor, from amongst teachers of the University or who has been teacher of any other university or any suitable person who shall not be below the rank of Professor, or equivalent experience on the recommendation of selection committee chaired by the Vicechancellor. He shall report to the Vice-chancellor.

(2) The terms and conditions of service of the Dean of Student Welfare (DSW) shall be such as may be specified by the Subsequent Statutes and Ordinances of the university.

(3) The Dean of Student Welfare (DSW) shall perform the following functions, with the approval of the Vice-chancellor.

- (i) to make arrangement for the student residence in various University Hostels and to supervise discipline of students, studying in the University classes;
- (ii) to plan, organize and supervise the co-curricular and cultural activities of the students in the University campus;
- (iii) to look after the Physical welfare and NCC and NSS activities of the students in the University campus;
- (iv) to deal with all matters pertaining to discipline among the University students on the campus, and outside, excepting those relating to their Academic work, which will be

dealt with by the Heads of Departments and/or the Dean of Studies and to recommend penalties as may be deemed necessary, after due enquiry;

- (v) to devise ways and means for promoting the well being of the University students—social, moral and emotional values inculcating among them, regard for great ideas, like loyalty to country, devotion to duty and pursuit of truth and achieving excellence in studies and other co-curricular activities and sports, etc;
- (vi) to have the overall charge and supervision of the Office of the Dean of Students Welfare; and
- (vii) to perform any other duty or function allotted to him by the Vice-Chancellor from time to time.

(4) The Vice-Chancellor may authorise any other person to exercise any or all of the duties of the Dean of Student Welfare in his absence.

11. Appointment, terms and conditions of service of the Dean of Postgraduate studies and his functions.—(1) There shall be appointed a Dean of Post Graduate Studies by the Vice Chancellor, from amongst teachers of the University or who has been teacher of any other university who shall not be below the rank of Professor or the equivalent research and industrial qualification, on the recommendations of the selection committee chaired by the Vicechancellor and confirmed by the Chancellor.

(2) The terms and conditions of service of the Dean of Post Graduate Studies shall be such as may be specified by the Subsequent statutes and ordinances of the university.

(3) The Dean of Post Graduate Studies shall exercise and perform the following powers and functions, with the approval of the Vice-chancellor and report directly to the Vice-Chancellor,

- (i) to organise and co-ordinate and conduct of postgraduate teaching research across faculty/school/colleges and departments of the university;
- (ii) to co-ordinate all Postgraduate academic activities at University level through respective Deans of faculties and Deans of Studies;
- (iii) to co-ordinate wherever necessary, the work of the teaching staff of the University Academic Departments but not to directly control, the work of the Deans of faculty, Deans of Studies and Heads of Departments in their respective departments;
- (iv) to act as an Academic guide, in developing and improving the teaching and research standards in the faculty/school/college Institutions/Departments;
- (v) to suggest and propose innovations and newer ideas in the working of the various educational processes and systems with a view to bring in latest technologies and ideas; and
- (vi) to perform any other duty or function allotted to him by the Vice-Chancellor and or the Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor may authorise any other person in the University to exercise any or all of the powers of Dean Post Graduate Studies in his absence.

12. The Librarian.—(1) Subject to the approval of the Chancellor, the Librarian shall be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Selection Committee chaired by the Vice-chancellor constituted by the Chancellor for the purpose and he shall be a whole time salaried officer of the University.

(2) The Librarian shall work under the control and supervision of the Vice-Chancellor and shall be responsible for the maintenance of all libraries of the University and for the organization of their services.

(3) The University Librarian shall have the following duties as approved by the Vice Chancellor, namely:—

- (a) he shall have general overall supervision of the University Library, and Library personnel and departments' libraries or collections;
- (b) he shall prepare the Library budget for the University Library including Department collections;
- (c) he shall have the responsibility of receiving and accessioning all library materials;
- (d) he shall have the responsibility of initiating the purchase requisition for all library materials;
- (e) he shall have the responsibility of renewing in time subscription to journals;
- (f) he shall prepare a library newsletter at monthly intervals which will carry a list of all library materials received since the last preceding newsletter and other timely library news of interest to students and staff;
- (g) he shall initiate, participate and co-operate in programme designed to stimulate and encourage the use of the library by the students and faculty;
- (h) he shall arrange library hours with the approval of Vice-Chancellor so as to permit maximum library use by both students and faculty members; and
- (i) he shall arrange for departments and other research centers, faculty/school/colleges and Institutions established and maintained by the University, small collections of volumes and journals that are in almost constant use by the faculty and postgraduate students as references/material.

13. Other Authorities of the University.— In addition to the authorities specified in the Section 17, there shall be the following other authorities of the University, namely:—

- (i) the Planning Board;
- (ii) the Finance Committee;
- (iii) the university Development Committee; and
- (iv) Alumni Relation Committee.

14. Term of office of the nominated Members of the Governing Body.—(1) The term of the office of the nominated members of the Governing Body under clauses (c) and (d) of section 18 shall be two years.

(2) If a nominated member under clause (1) ceases to be a member, new member shall be nominated for the remaining period.

(3) A nominated member may be re-nominated as a member of the Governing Body after the completion of the term.

(4) All decisions at the meeting shall be taken by a majority vote of the members present. The Chairperson at the meeting shall have a casting vote and a second vote in the case of equality.

15. Powers and Functions of the Governing Body.—In addition to the provisions of sub-section (3) of Section 18, the Governing Body shall have the following additional powers, namely:—

- (i) to approve the subsequent Statutes to be framed under section 27 and amendments there to as per provisions of Section 27 and the First Ordinances to be framed under section 28 by the Board of Management and amendments there to and the subsequent Ordinances to be framed under section 29 and amendments there to;
- (ii) to establish, equip and maintain a University library/laboratories;
- (iii) to provide for research and the advancement and dissemination of knowledge in such branches of learning as it may deem necessary; and
- (iv) to take all such measure and to do all such acts, as may be necessary or desirable to achieve the objects of the University.

16. Term of office of the nominated Members of the Board of Management.—(1) The term of the office of the nominated members of the Board of Management under clauses (b), (c) and (d) of Section 19 shall be three years.

(2) If a nominated member under clause (1) ceases to be a member, new member shall be nominated for the remaining period.

(3) A nominated member can be re-nominated as a member of the Board of Management after the completion of term.

(4) All decisions at the meeting shall be taken by a majority vote of the members present. The Chairman at the meeting shall have a casting vote in the case of equality.

(5) The undecided matters shall be forwarded to the Chancellor for decision and his decision shall be final.

17. Powers and functions of the Board of Management.—Under the provisions of the sub-section (3) of Section 19, the Board of Management shall exercise and perform following powers and functions, namely:—

(1) The Board of Management shall, subject to control of the Chancellor, have the power of management and administration of the revenue and property of the University and the conduct of all administrative affairs of the University not otherwise provided for.

(2) Subject to the provisions of the Act, the Subsequent Statutes and the Ordinances, the Board of Management shall, in addition to the other powers vested in it, have the following powers, namely:—

- (i) to approve teaching and other academic posts and to define the functions and conditions of service of Professors, Readers, Lecturers and other Teachers, and other academic staff employed by the University recommended by the Academic Council;
- (ii) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property of the University and all other affairs of the University and to appoint such agents as may be considered fit;
- (iii) to invest any money belonging to the University including any unapplied income, in such stocks, funds, shares or securities as it thinks fit or in the purchases of immovable property in India with like power of varying such investment from time to time, provided that no action under this clause shall be taken without consulting the Finance committee;
- (iv) to create administrative, ministerial and other necessary posts after taking into account the recommendations of the Academic Council, Finance Committee and to specify the number of appointments thereto;
- (v) to regulate and enforce discipline amongst the employees in accordance with the Subsequent Statutes and Ordinances;
- (vi) to transfer or accept transfers of any immovable property on behalf of the University;
- (vii) to entertain, adjudicate upon, or redress the grievances of the employees and the students of the University who may, for any reason, feel aggrieved;
- (viii) to select the common seal for the University and to provide for the use of such seal;
- (ix) to delegate any of its powers to the Vice-Chancellor, the Registrar, the Chief Finance and Accounts Officer, or to any other officer, employees or authority of the University, or to a committee appointed by it as it may deem fit;

(3) The Board of Management shall publish an annual report containing:—

- (i) a review of the progress made in different spheres of activities of the University;
- (ii) the amounts of receipts and disbursements and the purpose for which they were made;
- (iii) the number of officers, teachers and other employees and position and remuneration of each, the number of students in the several sections and classes and course of instruction pursued in each; and
- (iv) an estimate of the expenses for the next following year.

18. Constitution of the Academic Council.—(1) The Academic Council shall consist of the following persons, namely.—

(a) **Ex-officio members:—**

- (i) the Vice-Chancellor (Chairperson);
- (ii) the Dean(s) of Faculties of the University;
- (iii) the Dean of Studies;
- (iv) the Registrar (Member Secretary);
- (v) the Controller of Examinations;
- (vi) the Dean of Students Welfare;
- (vii) the Dean of Distant Education;
- (viii) the Dean of Postgraduate Studies;
- (ix) the Dean Co-operative Studies and Placement;
- (x) the Librarian; and
- (xi) the Directors of the institutes established by the university

(b) **Other members:—**

- (i) two persons, not being employees of the University, co-opted by the Academic Council for their special knowledge;
- (ii) the Registrar shall be the Member-Secretary of the Academic Council and shall not have right to vote;
- (iii) one-third of the members shall form the quorum;
- (iv) the members of the Academic Council, other than Ex-officio members, shall hold office for a term of two years;
- (v) all decisions at the meeting shall be taken by a majority vote of the members present. The Chairperson at the meeting shall have a casting vote in the case of equality; and
- (vi) the undecided matters shall be forwarded to the Chancellor and decision of the Chancellor shall be final.

19. Powers and function of the Academic Council.—(1) The Academic Council being principal Academic Body of the University shall, superintend, direct and control, and be responsible for the maintenance of standards of instructions, education and examinations and other matters connected with the obtaining of degrees and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be specified by the Subsequent statutes.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, and subject to the provisions of the Act, the Subsequent Statutes and the Ordinances, the Academic Council shall in addition to all other powers vested in it, have the following powers and duties, namely:—

- (a) to exercise general supervision over the academic policies of the University, and to give directives regarding methods of instructions, combined teaching among faculty/school/colleges, evaluation of research or improvements in academic standards;
- (b) to bring about Inter-Faculty co-ordination to establish or appoint committees for taking up projects on an Inter-Faculty basis;
- (c) to consider matters of general academic interests either on its own initiative or referred to it by a Faculty or Board of Management and to take appropriate action thereon;
- (d) to frame regulations in consonance with the Subsequent Statutes and Ordinances regarding the academic functioning of the University, discipline, residence, admissions, award of fellowships and studentships, fee concessions, attendance etc;
- (e) to recommend to the Board of Management the draft of new Ordinances or draft amendments to the existing Ordinances relating to,—
 - (i) the qualifications of teacher;
 - (ii) student participation in University/Faculty/school/college affairs and governance;
 - (iii) management of faculty/school/colleges and other institutions founded or maintained by the University;
 - (iv) degrees, diplomas, certificates, and other academic distinctions to be awarded by the University, qualifications for the same, the duration of the courses of study and other essential features of such courses and the type and nature of examination for such degrees, diplomas or certificates and other academic distinctions;
 - (v) the conduct of examinations, including the terms of office and the manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;
 - (vi) the admission of the students of the University and their enrolment, the maintenance of discipline among the students; the conditions regarding the residence of students;
 - (vii) the conditions for award of fellowships, scholarships, Stipend, medals and prizes;
 - (viii) the fees to be charged for courses of study and for admission to the examinations, degrees and diplomas of the University;
 - (ix) remuneration to be paid to examiners, moderators and tabulators, etc;
 - (x) creation, composition and functions of other bodies, committees, or boards necessary or desirable for improving the academic life of the University;
 - (xi) special arrangements, if any, for the residence, discipline and teaching of women students;
 - (xii) to recommend to the Chancellor introduction of a new subject(s) or opening of a new department(s)/Institute(s)/school(s)/centre(s) of studies in a particular Faculty/

Faculties. However, the Academic Council shall evaluate the performance of existing Faculty/Faculties before finally recommending to the Board of Management in the matter:

Provided that if the Board of Management disagrees with the Academic Council, it may adopt the draft in an amended form or reject it by a two-third majority of the members present and voting: and if the majority of two-third members is not available, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final:—

- (i) to prescribe number, qualifications and other eligibility conditions for teachers and other academic staff subject to the qualifications specified by UGC and other regulatory bodies;
- (ii) to specify the manner of appointment to temporary vacancies of academic staff;
- (iii) to provide for the appointment of visiting Professors, Emeritus Professors, Fellows, Artists, and Writers and determine the terms and conditions of such appointments;
- (iv) to fix the remuneration payable to course writers, counselors, examiners and invigilators and travelling and other allowances payable, after consulting the Finance Committee; and
- (v) to institute fellowships, scholarships, studentships; and

20. Meetings of the Academic Council.—(1) The meeting of Academic Council shall be held on such date and at such time and place as may be fixed by the Vice-Chancellor.

(2) The copies of the agenda of the meeting shall be supplied to the members at least fifteen days before the meeting.

(3) The quorum of the meetings of the Academic Council shall be one- third of its total members.

(4) All questions to be considered in a meeting of the Academic Council shall be decided by a majority of votes of the members present. The Chairman of the Academic Council shall be entitled to vote and in case of equality of votes the Chairman shall a second or casting vote.

21. Powers and duties of the planning Board.—(1) The Planning Board shall consist of the Vice-Chancellor and not more than six members to be nominated by the Chancellor.

(2) All the members of the Planning Board, other than the Vice-Chancellor, shall hold office for a term of three years.

(3) The Planning Board shall design and formulate appropriate plans for development and expansion of the University, and it shall, in addition, have the right to advise the Chancellor, Board of Management and the Academic Council on any matter which it may deem necessary for the fulfillment of the objects of the University.

(4) The Planning Board may constitute such committees as may be necessary for planning and monitoring the programmes of the University.

(5) The Planning Board shall meet at such intervals as it may deem expedient, but it shall meet at least twice in a year.

(6) The Vice-chancellor shall be the chairman of Planning Board.

(7) Decision to be taken by majority vote with chairman have second deciding vote in an event of equality.

22. Powers and duties of the Finance Committee.—(1) The Finance Committee shall consist of the following, namely:—

(a) the Vice-Chancellor,

(b) one person to be appointed by the Board of Management from amongst its members other than an employee of the University,

(c) three persons to be nominated by the Chancellor.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Finance Committee.

(3) The Chief Finance and Accounts Officer of the University shall be the exofficio Secretary of the Finance Committee and he shall have a right to vote.

(4) All members of the Finance Committee, other than the ex-officio Member, shall hold office for a term of three years from the date on which he becomes a member of the Committee.

(5) Three members of the Finance Committee shall form a quorum for a meeting of the Committee.

(6) The Finance Committee shall meet at least thrice in a year to examine the accounts and scrutinize the proposals for expenditure:

Provided that a period of not exceeding 180 days shall elapse between two consecutive meetings.

(7) All proposals relating to revision of grades, up gradation of the pay-scales and those items which are not included in the budget, shall be examined by the Finance Committee before those are considered by the Board of Management.

(8) The Finance Committee shall fix the limits for the total recurring and nonrecurring expenditure for the year, based on income and resources of the University, and no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits so fixed, without the approval of the Finance Committee.

(9) The annual accounts and the financial estimates of the University prepared by the Chief Finance and Accounts Officer shall be laid before the Finance Committee for consideration and comments and thereafter submitted, with or without amendments to the Board of Management within the overall ceiling fixed by the Committee.

23. The Faculties.—(1) The University shall have such Faculties as may be specified by the Subsequent Statutes.

(2) Each Faculty shall consist of such colleges/schools/departments of studies as may be assigned to it by the Ordinances.

(3) No department shall be established or abolished except by the Subsequent Statutes.

24. MISCELLANEOUS PROVISIONS CONCERNING AUTHORITIES :

(1) **Other Committees.**—The Governing Body or the Academic Council may appoint such Boards or Committees consisting of members of the Governing Body or Academic council making such appointment may appoint such other persons as that Authority in each case may think fit; and any such Board or Committee may deal with any such subject assigned to it subject to subsequent confirmation by the Authority which appointed it.

(2) **Elected Chairman to preside where no provision is made in the Statutes.**—Where, by the Act, the Statutes or the Ordinances, no provision is made for a Chairman to preside over a meeting of any University Authority, Board or Committee, or when the Chairman so provided for is absent, the members present shall elect one among them to preside at the meeting.

(3) **Resignation.**—(i) Any member other than an ex-officio Members of the Governing Body, the Board of Management, the Academic Council or any other Authority of the University or Committee may resign by a letter addressed to the Registrar and the resignation shall take effect as soon as letter is received by the Registrar;

(ii) Any Officer of the University (whether salaried or otherwise) may resign his office by a letter addressed to the Registrar:

Provided that such resignation shall take effect only on the date from which the same is accepted by the Authority competent to fill the vacancy.

(iii) If any member of the Authority of the University ceases to be a member of the body from which he has been elected/nominated or appointed he shall cease to be the member of that authority.

25. The manner of appointments and removal of teaching posts.—(1) The teachers of the University shall be appointed by the Vice-chancellor on the recommendation of selection committee with the approval of the Chancellor.

(2) The Academic Council may, by a special resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw recognition of a teacher:

Provided that no such resolution shall be passed until a notice in writing has been given to that teacher calling upon him to show cause, within such time as may be specified in the notice as to why such resolution should not be passed and until his objections, if any, and any evidence he may produce in support of them, have been considered by the Academic Council.

(3) No person shall be appointed or recognized as a teacher of the University for the Regular Post except on the recommendations of a Selection Committee constituted for the purpose.

(4) The Vice-chancellor shall be authorized to make need based adhoc/contract appointments for a period not to exceed one year.

26. Selection Committee.—(1) There shall be Selection Committees for making recommendations for appointments to the posts of the Professor, Reader (Associate Professor), Assistant Professor, Lecturer, Registrar, Controller of Examinations, Finance Officer and the Librarian.

(2) Every such Selection Committee shall consist of the Vice-Chancellor who shall be the Chairman thereof, and person(s) nominated by the Chancellor and, in addition, the Selection

Committee for making recommendations for appointment to a post specified in column (1) of the table below shall have as its members the persons specified in the corresponding entry in column (2) of the said table:

Professor/Reader (Associate Professor).—(i) The Head of the Department concerned if he is Professor.

(ii) Two persons not connected with the University, nominated by the Chancellor, out of a panel of the names recommended by the Vice Chancellor for their special knowledge of or in the subject with which the Professor will be concerned.

Assistant Professor/Lecturer.—(i) The Head of the Department concerned.

(ii) Two persons not connected with the University, nominated by the Chancellor out of a panel of the names recommended by the Vice Chancellor for their special knowledge of or in the subject with which the Assistant Professor or Lecturer will be concerned.

Registrar/Controller of Examination/Chief Finance and Account officer.—Three persons nominated by the Chancellor. One member each should be an expert in an Academic Administration, Management and Finance respectively.

Librarian.—Two persons connected with the University, who have special knowledge of the subject or Library Science to be nominated by the Chancellor.

(3) The recommendations of the Selection Committee shall be subject to the regulations issued by the University Grants Commission or other regulatory bodies as the case may be, from time to time, with regard to appointment and promotion of Professors, Reader (Associate Professors), Lecturers and administrative posts of the University.

(4) The recommendations of the Selection Committee shall be subject to the regulations issued by the University Grants Commission or other regulatory bodies as the case may be, from time to time, with regard to appointment and promotion of Professors, Reader (Associate Professors), Lecturers and administrative posts of the University.

27. The manner of appointments of non-teaching posts.—(1) All Candidates to non-teaching posts shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of the Selection committee consisting of:—

- (i) the Vice-Chancellor (Chairperson);
- (ii) two members nominated by the Board of Management; and
- (iii) the Registrar.....Member Secretary.

(2) The member Secretary of the committee shall keep record of its proceedings and shall perform such other functions as may be assigned to him by the Vice-Chancellor.

28. Terms and Conditions of Service of the teaching posts.—(1) All the teachers and other academic staff of the University shall, in the absence of any agreement to the contrary, be governed by the terms and conditions of service as are specified in the Statutes made by the University Subsequently.

(2) The emoluments of members of the academic staff shall be such as may be specified in the Statutes made by the University subsequently.

(3) Every teacher and member of the academic staff of the University shall be appointed on a written contract, the form of which shall be specified in the Statutes made by the University subsequently.

(4) A copy of every contract referred to in clause (3) shall be deposited with the Registrar.

(5) Any dispute arising out of a contract between the University and those mentioned in clause (1) shall at the request of the teacher or the officer or employee concerned, or at the instance of the University be referred to a Committee consisting of one member appointed by the authority competent to make the appointment, one member nominated by the employee concerned and an umpire appointed by the Chancellor and the decision of the Committee shall be final.

29. Removal of Teachers.—(1) Where there is an allegation of misconduct against a teacher, the Vice-Chancellor may, if he thinks fit, by order in writing place the teacher under suspension and shall forthwith report to the Chancellor the circumstances under which the order was made:

Provided that the Chancellor may, if he is of the opinion that the circumstances of the case do not warrant the suspension of the teacher, revoke that order.

(2) Notwithstanding anything contained in terms of his contract of service or of his appointment, the Chancellor shall be entitled to remove a teacher on the ground of misconduct.

(3) Save as aforesaid, the Chancellor shall not be entitled to remove a teacher except for a good and sufficient cause and after giving three months notice in writing or payment of three months' salary in lieu of notice.

(4) No teacher shall be removed under clause (2) or under clause (3) until he has been given a reasonable opportunity to show cause against the action proposed to be taken with regard to him.

(5) The removal of a teacher shall take effect from the date on which the order of removal is made:

Provided that where a teacher is under suspension at the time of his removal, the removal shall take effect on the date on which he was placed under suspension.

(6) Notwithstanding anything contained in these Statutes, a teacher shall be entitled to resign by giving three months notice in writing to the Vice-Chancellor.

30. Terms and Conditions of Service of the Non-teaching posts.—(1) All the employees of the University, other than the teachers and other academic staff shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service as are specified in the Statutes made by the University subsequently.

(2) The manner of appointment and emoluments of employees, other than the teachers and other academic staff, shall be such as may be specified in the Statutes made by the University subsequently.

31. Removal of employees other than a teacher.—(1) Notwithstanding anything contained in terms of his contract of service or of his appointment, an employee, other than a teacher, may be removed by the authority which is competent to appoint the employee if he has incurred any disqualifications under section 22;

- (a) he is of unsound mind and stands so declared by a competent authority;
- (b) he is an un-discharged insolvent;
- (c) he has been convicted by the court of law of any criminal offence or an offence involving moral turpitude; and
- (d) he is otherwise guilty of proven misconduct:

Provided that no employee shall be removed without the approval of the Chancellor.

(2) No employee shall be removed from service under clause (1) until he has been given a reasonable opportunity to show cause against the action proposed to be taken with regard to him.

(3) Where the removal from service of an employee is for a reason other than that specified of clause(1), he shall be given three months notice in writing or paid three months salary in lieu of notice, provided the employee is a permanent regular employee. In case of employee who is on probation only one month notice is required.

(4) Notwithstanding anything contained in these Statutes, an employee, other than a teacher, shall be entitled to resign unless he,—

- (i) gives a three months' notice in writing to the appointing authority or pays to the University three months' salary in lieu of notice if he is a permanent employee; and
- (ii) gives a one months' notice in writing to the appointing authority or pays to the University one month salary in lieu thereof in any other case.

32. Code of Conduct for Employees.—(1) Every employee shall, at all times maintain absolute integrity and devotion to duty, and also be strictly honest and impartial in his official dealings.

(2) An employee shall at all times be courteous in his dealings with other members of the staff, students and general public.

(3) Unless otherwise provided specifically in the terms of appointment, every employee is a whole-time employee of the University, and may be called upon to perform such duties, as may be assigned to him by the concerned authority or officer, beyond scheduled working hours and on holidays and during vacations. These duties shall inter alia include attendance at meeting of committees to which he may be appointed by the University.

(4) An employee shall be required to observe the scheduled hours of work, during which he is required to be present at the place of his duty.

(5) Except for valid reasons and or unforeseen contingencies no employee shall be absent from duty without prior written permission.

(6) No employee shall leave station except with the previous written permission of proper authority, even during leave or vacation.

(7) Whenever leaving the station, an employee shall inform the Head of the Department to whom he is attached, or Dean of Studies if he is himself the Head of a Department, of the address where he would be available during the period of the absence from station.

(8) No employee shall take active part in politics in the campus of the University or exploit his official position or permit the use of University facilities for political purposes.

(9) No employee shall, in any broadcast or in any document published anonymously or in his own name or in the name of any other person or in any communication to the press or in any public utterance, make any statement of fact or opinion;

- (i) which has the effect of an adverse criticism of any policy or action of the University; or
- (ii) which is capable of embarrassing the relations between the University and the Central Government or any State Government or any other Institution or organization or members of public; or
- (iii) which exploits the name of the University or his position therein;
- (iv) Nothing in this paragraph shall apply to any statements or views expressed by an employee in his official capacity or in the due performance of the duties assigned to him.

(10) Save as provided in sub-paragraph (c) (iii) of this para.—

- (a) no employee shall, except with the previous sanction of the concerned authority, give evidence in connection with any inquiry conducted by any person, Committee or authority.
- (b) where any sanction has been accorded under sub-paragraph c (i) no employee giving such evidence shall criticize the policy or any action of the University or the Central Government or any State Government.

(c) nothing in this paragraph shall apply for :—

- (i) evidence given at any inquiry before any authority appointed by the University, by Parliament or by a State Legislature; or
- (ii) evidence given in any judicial inquiry; or
- (iii) evidence given at any departmental enquiry ordered by the University authorities.

(11) No employee shall, except in accordance with any general or special order of the concerned authority or in the performance in good faith of the duties assigned to him, communicate, directly or indirectly, any official document or information to any person to whom he is not authorized to communicate such document or information.

(12) No employee shall, except with the previous written permission of the concerned authority, engage directly or indirectly, in any trade or business or undertake any employment outside his official assignments.

(13) No employee shall speculate in any business nor shall make or permit his spouse or any members of his family to make, any investment likely to embarrass or influence him in the discharge of his official duties and shall lend money at interest to any person nor shall he borrow money from any person with whom he is likely to have official dealings.

(14) An employee shall so manage his private affairs as to avoid habitual indebtedness or insolvency. When an employee is found liable to arrest for debt or has recourse to insolvency or when it is found that a moiety of his salary is continuously being attached, he may be liable to dismissal. Any employee, who becomes the subject of legal proceedings for insolvency shall forthwith report full facts to the University authorities. In case any employee who gets involved in some criminal proceedings shall immediately inform the competent authority through the Head of the Department to which he is attached, irrespective of the fact whether he has been released on bail or not and the employee who is detained in police custody whether on criminal charge or otherwise for a period longer than 48 hours shall not join his duties in the University unless he has obtained written permission to that effect from the Dean of Studies of the Institution.

(15) Every member of the staff shall, on first appointment in the University service and thereafter at such intervals as may be prescribed by general or special orders of the concerned authority, submit return in such form as the University may prescribe in this behalf, of all movable and immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person.

(16) No employee shall, except with the previous sanction of the concerned authority, have recourse to any court of law or to press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or an attack of defamatory character:

Provided nothing in this para shall be deemed to prohibit an employee from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity.

(17) Whenever an employee wishes to put forth any claim, or seeks redress of any wrong done to him, he shall forward his case through proper channel, and shall not forward such advance copies of his representation to any higher authority, unless the lower authority has rejected the claim or refused relief, or the disposal of the matter is delayed by more than three months; provided that no employee shall be signatory to any joint representation addressed to the authorities for redress of any grievances or for any other matter.

(18) An employee shall be governed by the provisions of the Statutes made by the University subsequently regarding imposition of penalties for breach of any of conduct rules or otherwise and preferring an appeal against any such action taken against him.

33. The procedure for arbitration.—(1) In case of any dispute arising between the University and an employee of the University and the same remains undecided for a period more than one year then the same shall be, on the request of either party, referred to a Arbitral Tribunal for decision, which shall consist of the following :—

- (i) a Chairman nominated by the Chancellor;
- (ii) one person nominated by the Board of Management; and

(iii) one person nominated by the employee concerned.

(2) The University shall furnish any record, report or other information called for by the Arbitral Tribunal to discharge its function in an efficient manner.

(3) The decision of the Arbitral Tribunal shall be final and no suit shall lie in any civil court in respect of the matter decided by it.

(4) Any student or candidate for an examination whose name has been removed from the rolls of the University by the orders or resolution of the Vice-Chancellor, Discipline Committee or Examination Committee, as the case may be, and who has been debarred from appearing at the examination of the University for more than one year, may, within ten days of the date of receipt of such orders or copy of such resolution by him, appeal to the Chancellor and the Chancellor may confirm, modify or reverse the decision of the Vice-Chancellor or the Committee, as the case may be and any dispute arising out of any disciplinary action taken by the University against a student shall, at the request of such student, be referred to a Arbitral Tribunal as specified in the Ordinances/Regulations.

(5) Every employee or student of the University or Institution maintained by the University shall, notwithstanding anything contained in this Act, have a right to appeal within such time as may be specified by the Statutes made by the University subsequently, to the Chancellor against the decision of any officer or authority of the University or of Institution, as the case may be, and thereupon, the Chancellor may confirm, modify or reverse the decision appealed against.

(6) All disputes shall be subject to jurisdiction of the Civil Courts, Rajgarh, District Sirmour, Himachal Pradesh.

(7) No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of the Act or the Statutes or the Ordinances made under the Act.

34. Maintenance of discipline among students of the University.—(1) All powers relating to discipline and disciplinary action are vested in the Vice-Chancellor.

(2) The Vice-Chancellor may delegate all or such powers as he deems proper to such other persons as he may specify in this behalf.

(3) Without prejudice to the generality of powers to enforce discipline under the Statute, the following will amount to act of gross indiscipline:—

(a) physical assault, or threat to use physical force, against any member of the teaching and non-teaching staff of any institution, department against any student or any other person within, the University;

(b) carrying or use of, or threat of use of any weapon;

(c) any violation of the provisions of the Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955);

(d) violation of the status, dignity and honour of students belonging to the Schedule Castes and Tribes;

- (e) any practice whether verbal or otherwise derogatory to women;
- (f) any attempt to bribe or corruption in any manner;
- (g) Wilful destruction of institution and property;
- (h) creating ill or intolerance on religious or communal grounds;
- (i) causing disruption in any manner of the academic functioning of the University system; and
- (j) ragging.

(4) Without prejudice to the generality of his powers relating to the maintenance of discipline and taking such action in the interest of maintaining discipline as may seem to him appropriate, the Vice-Chancellor, may in the exercise of his powers aforesaid order or direct that any student or students:—

- (a) be expelled; or
- (b) be, for a stated period rusticated; or
- (c) be not for a stated period, admitted to a course or courses of study in a Faculty/school/college, Department or Institution of the University; or
- (d) be fined with a sum of rupees that may be specified, or
- (e) be debarred from taking a University or Faculty/school/college or Departmental Examination or Examinations for one or more years; or
- (f) that the result of the student or students concerned in the examination or examination in which he or they have appeared be cancelled.

(5) The Dean of the Faculty/school/colleges, Head of the Halls, Deans of Faculties, Heads of Teaching Departments in the University, the Head of the Distant Education and the Librarian shall exercise disciplinary authority over students in their respective Faculty/school/colleges, Institutions, Faculties and Teaching departments, in the University as may be necessary for the proper conduct of the Institutions, residence halls and teaching in the concerned Departments subject to the approval of the Vice-chancellor.

(6) Without prejudice to the powers of the Vice-Chancellor and the officers as aforesaid, detailed Regulations of discipline and proper conduct shall be framed by the University.

(7) At the time of admission, every student shall be required to sign a declaration that on admission he submits himself to the disciplinary jurisdiction of the Vice-Chancellor and the other authorities of the University who may be vested with the authority to exercise discipline under the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations that have been framed thereunder by the University.

35. Prohibition of and Punishment for Ragging.—(1) Ragging in any form shall be strictly prohibited, within the premises of University or Faculty/school/college or Institution or outside the faculty/school/college.

(2) Any individual or collective act or practice of ragging shall amount to a gross indiscipline and shall be dealt with under this Statute.

(3) Ragging for the purposes of this Statute, ordinarily means any act, conduct or practice by which dominant powers or status of senior students is brought to bear on students freshly enrolled or students who are in, way considered junior or inferior by other students and includes individual or collective acts or practices which:—

- (a) Involve physical assault or threat to use of physical force;
- (b) violate the status, dignity and honor of women students;
- (c) violate the status, dignity and honor of students belonging to the Scheduled Castes and Tribes;
- (d) expose students to ridicule and contempt and affect their self esteem; and
- (e) entail verbal abuse and aggression, indecent gestures and obscene behaviour.

(4) The Dean of a Faculty/school/college, the Head of the Department or an Institution, the authorities or Faculty/school/college or University Hostel or Halls of Residence shall take immediate action on any information of the occurrence of ragging.

(5) Notwithstanding anything in Clause (4), the officer may also enquire into any incident of ragging and make a report to the Vice-Chancellor of the identity of those who are engaged in ragging and the nature of the incident.

(6) The Officer may also submit to the Vice-chancellor an initial report establishing the identity of the perpetrators of ragging and the nature of the ragging incident.

(7) If the Dean of a Faculty/school/college or Head of the Department or Institution is satisfied that for some reason, to be recorded in writing, it is not reasonably practical to hold such an enquiry, he may so advise the Vice-Chancellor accordingly.

(8) When the Vice-Chancellor is satisfied that it is not expedient to hold such enquiry, his decision shall be final.

(9) On receipt of a report under Clause (5) or (6) or a determination by the relevant authority under Clause (7) disclosing the occurrence of ragging incidents described in Clause 3(a), (b) and (c), the Vice-Chancellor shall direct or order rustication of a student or students for a specific number of years.

(10) The Vice-Chancellor may in other cases of ragging order or direct that any student or students be expelled or be not for a stated period, admitted to a course of study in a Faculty/school/college, Departmental Examination for one or more years or that the result of the student or students concerned in the examination or examinations in which they appeared be cancelled.

(11) In case any students who have obtained degrees of the University are found guilty under this Statute, appropriate action for withdrawal of degrees conferred by the University shall be initiated.

(12) For the purpose of this Statute, abetment of ragging whether by way of any act, practice or incitement of ragging shall also amount to ragging.

(13) All institutions within the University system shall be obligated to carry out instructions/directions issued under the Statute, and to give aid and assistance to the Vice-Chancellor to achieve the effective implementation of the Statute.

36. Conferment of Honorary Degrees and Academic Distinctions.—(1) The Academic Council on the recommendations of the Vice-chancellor and subject to confirmation by the Chancellor, to confer honorary degrees and other academic distinctions on persons by virtue of their eminence and attainments in industry or contributions to the cause of social/community service/learning in science, humanities, engineering, technology, management, education, pharmacy, hospitality, media, fashion, architecture, fine arts or have established position in the industrial/scientific world and who are considered fit and proper to receive such honorary degrees.

(2) All recommendation of the Academic Council for conferment of honorary degrees and distinctions shall be made through a Committee consisting of the Vice-Chancellor and two other members appointed by the Board of Management subject to the confirmation of the Chancellor.

(3) The honorary degrees or distinctions shall be conferred at convocation and may be taken in person or in absentia.

(4) The presentation at convocation of persons on whom honorary degrees are to be conferred shall be made by the Vice-Chancellor or by any other person nominated by the Chancellor for the purpose.

(5) The Board of Management shall have the authority to make or alter the rules of procedure to be followed at such convocation.

(6) The Academic Council may, by a special resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw any degree of academic distinction conferred on, or any certificate or diploma granted to, any person by the University for good and sufficient cause:

Provided that no such resolution shall be passed until, a notice in writing has been given to that person calling upon him to show cause within such time as may be specified in the notice as to why such resolution should not be passed and until his objections, if any, and any evidence he may produce in support of them, have been considered by Academic Council.

37. Institution of Fellowships, Scholarships, Studentships, Medals, Prizes, etc.—(1) The Academic Council shall initiate action in consultation with the appropriate Faculty of each Institute and recommend the instituting of tuition freeships, fellowships, scholarships, studentships, medals, prizes, etc. The recommendations of the Academic Council shall recommend these awards to the Chancellor for confirmation.

(2) It shall be the responsibility of the Dean of Faculty of the Institute to ensure sufficient provision in the budget of his Institute for such of the schemes approved by the Academic Council.

(3) The Board of Management shall have full powers to make rules and regulations for the purposes of award, suspension, or cancellation of the tuition free ship, fellowships, scholarships, studentships, medals, prizes and others approved by it:

Provided that the existing schemes of tuitions freeships, fellowships, scholarships, studentships, medals, prizes, Merit-cum-Means Scholarships, Educational Loans and other

concessions shall continue to be in force in respect of each of the constituent Institutes until such time as they are replaced, altered or otherwise dealt with by the Chancellor

(4) The tuition fee concessions may be granted on the basis of merit as may be decided by the Academic Council from time to time.

39. Admission policy.—(1) Subject to provisions of the Act and any other law for the time being in force, the admissions in the Under-Graduate/Integrated/Post-Graduate/Doctoral programs shall be made strictly on the basis of merit/rank in the entrance examination conducted at state level/All India level and marks/grades obtained in the qualifying examination and achievements in co-curricular activities. In case no entrance test is conducted at state level/All India level for a program, the University may conduct its own entrance test.

In case no examination is conducted by the University, merit in the qualifying examination shall be the criterion for admission. The eligibility criteria and procedure for admission in various programs run by the University shall be specified through the Ordinances/Regulations from time to time.

(2) 25% seats shall be reserved for the candidate in all the courses for bonafide Himachali. University shall reserve seats for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Physically Handicapped and other socially and educationally backward classes to such extent as notified by the Government of Himachal Pradesh from time to time:

Provided that in case seat(s) allotted under reserved categories remain vacant, the seat(s) shall be converted to General category and offered to the candidates belonging to the General category.

39. Provisions regarding fees to be charged from the students—In addition to the provision made under Section 32 of the Act, the following procedure shall be adopted to decide the fee structure.—(1) The University shall charge such fees from the undergraduate, postgraduate, research and post-doctoral students for different Academic programmes as may be determined by the Finance Committee with the approval of the Chancellor.

(2) The University shall also award fee waivers to the Students and research scholars in accordance with the recommendations of Academic Council and with approval of the Chancellor.

(3) The procedure for the deposition of fees, delay fine, entry/deletion, of the names from the rolls of the academic programmes of the Institute, and such other matters as may be decided by the Academic Council, shall be laid down in the Ordinances.

(4) The University fee shall be charged under the following main categories:—

- (a) Admission fee.
- (b) Tuition fee.
- (c) Medical fee.
- (d) Examination fee.
- (e) Students Service Fund.
- (f) University Registration fee.

- (g) Institutional Development Fund.
- (h) Caution Money (Refundable, One time, at the time of admission only).
- (i) Contribution to such educational, social and recreational funds as may be specified.
- (j) Transport fees (as required).
- (k) Hostel fees (as required).
- (l) Any other fee prescribed from time to time.

(5) The following documents shall be issued by the University on the request of the students on the specified Performa along with the fee as may be fixed by the Board of Management from time to time:—

- (a) Duplicate certificate/Degree.
- (b) Provisional Certificate/Degree.
- (c) Merit Certificate.
- (d) Detailed marks Card (DMC).
- (e) Duplicate DMC.
- (f) Admission form.
- (g) Transcript.
- (h) Re-appear form.
- (i) Re-evaluation form.
- (j) Examination form.
- (k) Registration form.
- (l) Migration Certificate.
- (m) Confidential result.
- (n) Any other document required by the student.

(6) the Board of Management shall have the power to revise, from time to time, the rates of various fees, fines and other charges fixed and to also specify additional fees, fines and other charges, as may be determined, from time to time.

40. Provisions regarding number of seats in different courses.—(1) Total number of seats in different courses shall be decided by the Academic Council and approved by the Chancellor. However, reservation of seats for different categories in each course shall be kept as per Govt. rules and vacancies in different categories may be filled by open category candidates.

(2) Number of seats in different courses may be increased or decreased at the discretion of the Academic Council subject to approval of the Chancellor.

(3) The distribution of seats in different courses shall be decided by the Academic Council with the approval of the Chancellor.

41. Dean of Academic Affairs.—The Dean of Academic Affairs shall report directly to the Vice-Chancellor and perform the following functions:

- (1) Developing syllabi of new academic programmes to be established by various faculties/schools/colleges/institutions of the University.
- (2) Update syllabi of existing academic programmes of various programmes of the University.
- (3) Develop inter-discipline and joint degree academic programmes and their syllabi.
- (4) Seek accreditation from the appropriate accrediting/professional agencies both national and international agencies.
- (5) Develop academic collaboration for the University with Institutions of repute both in India and abroad.
- (6) Recommend to the Vice-Chancellor about the establishment of new academic programmes and for the elimination of certain other programmes.
- (7) To control and implement the various scholarships schemes of State/Central Government for Campus students;
- (8) To publish In-house magazines and other similar publications as their Chief Editor and Coordinator; and

42. Dean of Faculty.—The Dean of Faculty shall report directly to the Vice-Chancellor and shall perform the following functions:

- (1) Shall oversee the functioning and development of academic units (schools, departments, institutions) under the faculty and shall co-ordinate with the Dean of Academics in performing such duties.
- (2) Shall advise the Vice-Chancellor *vis-à-vis* all academic and administrative matters of faculty under him.
- (3) The heads of various academic units, i.e., departments, schools, colleges, institutions with the faculty, shall report to him on a regular basis.

43. Dean of Co-operative Studies and Placement.—The Dean of Co-operative Studies and Placement shall report to Vice-Chancellor and perform the following duties and functions:

- (1) To identify institutions of higher learning and training centers where students could be placed under co-operative academic education and practical training arrangements with prospective employers.

(2) Under this arrangement a select number of students shall study a part of a academic year at the Eternal University and spend a part of Academic Year at the training site. At the end of this co-operative arrangement of academic training and practical training, may lead to placement opportunities.

44. Dean of Distance Learning.—The Dean of Distance Learning shall report to Vice-Chancellor and will be incharge of all academic programmes under the university. His duties will be established as specified in subsequent statute.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.